



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 254]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 31, 2010/भाद्र 9, 1932

No. 254]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 31, 2010/BHADRA 9, 1932

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी तथा संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2010

मध्यावधि समीक्षा

विषय : चीन जन.गण., चीनी ताइपेई तथा इंडोनेशिया के मूल के या वहां से निर्यातित मैलिक एनहाइड्राइड (एम ए एन) से संबंधित पाटनरोधी जांच के बारे में मध्यावधि समीक्षा जांच परिणाम

सं. 15/11/2009-डीजीएडी.—पृष्ठभूमि

1. इस जांच के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई गई है :

- (i) मूल जांच के संबंध में अंतिम जांच परिणाम 22 अगस्त, 2008 की अधिसूचना सं. 14/3/2007-डी जी ए डी के तहत जारी किए गए थे तथा अंतिम जांच परिणामों का शुद्धिपत्र 5 सितम्बर, 2008 को जारी किया गया था और यतः संबंध देशों के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु पर 18 सितम्बर, 2008 की सी.शु. अधिसूचना सं. 105/2008-सी.शु. के तहत निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था।
- (ii) घरेलू उद्योग मै. तिरूमलाई कैमिकल्स लि. (टी सी एल), रानीपेट ने चीन जन.गण., चीनी ताइपेई और इंडोनेशिया के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु मैलिक एनहाइड्राइड (एम ए एन) के आयातों के संबंध में 8 सितम्बर, 2008 की सी.शु. अधिसूचना सं. 105/2008 के तहत लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की मध्यावधि समीक्षा हेतु एक आवेदन प्रस्तुत किया है। घरेलू उद्योग ने यह बताया था कि पाटित आयातों से सुरक्षा के अभाव में टी सी एल (मै. तिरूमलाई कैमिकल्स लि.) को शुल्क लगाए जाने से पूर्व अपने सम्पूर्ण प्रचालन बंद करने के लिए बाध्य होना पड़ा था। यह बताया गया था कि कंपनी अपने संयंत्र में मैलिक एनहाइड्राइड का उत्पादन कर रही है। कंपनी अत्यधिक उत्पादन लागत तथा सस्ते आयातों के कारण कीमत में भारी कटौती की वजह से अपना प्रचालन बंद करने के लिए बाध्य

- हुई । कंपनी ने डी जी सी आई एंड एस के आधार पर पूर्ववर्ती वर्षों (2005-06, 2006-07 तथा 2007-08) और आई बी आई एस के आधार पर 2008-09 की अवधि के लिए आयात आंकड़े उपलब्ध कराए हैं । एक अन्य उत्पादक अर्थात् मै. मैसूर पेट्रोकेमिकल्स लि. का समर्थन पत्र भी प्रदान किया गया है और यह बताया गया है कि कंपनी जांच की शुरुआत होने पर सूचना प्रदान कर देगी । कंपनी ने इन परवर्तित परिस्थितियों में मध्यावधि समीक्षा की शुरुआत हेतु अनुरोध किया है ।
- (iii) मै. पालिस्टर रेजिन मैन्यु. एसो. ने परिवर्तित परिस्थितियों के कारण मध्यावधि समीक्षा शुरू करने का अनुरोध किया है क्योंकि मै. टी सी एल ने मैलिक एनहाइड्राइड का उत्पादन बंद कर दिया है और कोई घरेलू उद्योग नहीं है । उन्होंने अपने दावे के समर्थन में जनवरी-अक्टूबर, 2009 की अवधि के लिए आई बी आई एस के आधार पर आयात के आंकड़ों की प्रतियां प्रस्तुत की हैं । यह अनुरोध किया गया है कि आई बी आई एस से उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर घरेलू उद्योग (टी सी एल) ने मलेशिया स्थित अपने संयंत्र से संबद्ध वस्तु का सीधे अथवा अपने एजेंटों के जरिए और मै. रेनसम पी टी ई लि., सिंगापुर, जो उनकी सहायक है, के जरिए भारी मात्रा में आयात किया है । यह तर्क दिया गया है कि इस उत्पाद को सिंगापुर में कोई प्रचालनरत संयंत्र नहीं है जिससे स्पष्टतः यह पता चलता है कि ये वस्तुएं मलेशिया के मूल की हैं और इन्हें मात्र सिंगापुर होकर लाया गया है । मलेशिया से ऐसे आयातों के कारण टी सी एल ने भारत में अपनी उत्पादन सुविधाएं बंद कर दी हैं । यह निवेदन किया गया है कि भारत में संबद्ध पण्य वस्तु का कोई घरेलू उत्पादन नहीं होता है इसलिए पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति की भरपाई हेतु पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना एकमात्र तर्काधार है ।
- (iv) मै. इंडियन प्लास्टिसाइजर्स मैन्यु. एसो. ने भी उपर्युक्त मामले में पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा का अनुरोध किया है । यह अनुरोध किया है कि वर्ष 2007-08 तथा 2008-09 के लिए मै. टी सी एल द्वारा दर्शाया गया उत्पादन उनके खुद के आयात की वजह से है जिसका सत्यापन आयात के आंकड़ों से किया जा सकता है । वस्तुतः टी सी एल ने मैलिक एनहाइड्राइड का उत्पादन छोड़ दिया है । उनकी वार्षिक रिपोर्ट, 2008-09 में यह बताया गया है कि उन्होंने मैलिक एनहाइड्राइड का उत्पादन बंद कर दिया है और इस उत्पाद की उनकी आबद्ध जरूरत की पूर्ति आयातों द्वारा की जा रही है क्योंकि आयात उत्पादन की तुलना में अधिक किफायती तथा व्यवहार्य हैं । यह बताया गया है कि टी सी एल द्वारा इस उत्पाद का आयात अपनी सहयोगी कंपनी अर्थात् बी एम जी कैमिकल्स प्रा.लि. के जरिए किया जा रहा है । उन्होंने अगस्त-नवंबर, 2009 के लिए तथा वर्ष 2008-09 की वार्षिक रिपोर्ट के संगत भाग से मैलिक एनहाइड्राइड के आयात के आंकड़े प्रस्तुत

किए हैं। उपर्युक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लागत पाटनरोधी उपायों की समीक्षा आवश्यक है।

- (v) आवेदकों द्वारा प्रदत्त सूचना को ध्यान में रखते हुए जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि परिवर्तित परिस्थितियों में लागे उपाय की समीक्षा आवश्यक हो गई है, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने यह माना कि 22.8.2008 की अधिसूचना सं. 14/3/2007-डी जी ए डी द्वारा अधिसूचित अंतिम जांच परिणामों और 18 सितंबर, 2008 की सी.शु. अधिसूचना सं. 105/2008 द्वारा लगाए गए निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क की मध्यावधि समीक्षा उपर्युक्त नियम 23 के साथ पठित सीमामशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 की धारा 9 (क) के उपबंध के अनुसार परिवर्तित परिस्थितियों के मद्देनजर उचित है। तदनुसार यह समीक्षा 11 फरवरी, 2010 की अधिसूचना सं. 15-11-2009-डी जी ए डी के तहत शुरू की गई थी। इस समीक्षा में 22.8.2008 की अधिसूचना सं. 14/3/2007-डी जी ए डी के सभी पहलू शामिल हैं।
- (vi) प्राधिकारी ने 11.02.2010 की जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना की प्रतियां उपलब्ध पतों के अनुसार भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों, संबद्ध देशों के ज्ञात निर्यातकों, आयातकों एवं घरेलू उद्योग को भेजी और उनसे जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना के 40 दिन के भीतर लिखित में अपने विचारों से अवगत कराने का अनुरोध किया।
- (vii) प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियम 6(3) के अनुसार आवेदन के अगोपनीय रूपांतरण की प्रतियां ज्ञात निर्यातकों तथा संबद्ध देशों के दूतावासों को उपलब्ध कराईं।
- (viii) प्राधिकारी ने नियम 6(4) के अनुसार संगत सूचना मांगने के लिए संबद्ध देशों के ज्ञात निर्यातकों को प्रश्नावलियां भेजीं।
- (ix) उपर्युक्त अधिसूचना के उत्तर में उपर्युक्त एसो. तथा घरेलू उद्योग ने उत्तर दिया है।
- (x) उपर्युक्त अधिसूचना के उत्तर में सांक्षी रिजेंट वर्क्स, चीन जन.गण. की ओर से मै. डी डी इंटरनेशनल को छोड़कर किसी भी निर्यातक ने प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है।
- (xi) आयातकों अर्थात् मै. जयदीप एजेंसीज, मेकेमको रेजिन्स प्रा.लि., रचना प्लास्टिसाइजर्स, के एल जे सिल्वेसा प्लास्ट, विसेन इंडस्ट्रीज ने उत्तर दिया है

और उनके द्वारा वर्ष 2006-07, 2007-08 तथा जांच अवधि के दौरान किए गए आयातों के संबंध में सूचना प्रदान की है।

- (xii) वर्तमान मध्यावधि समीक्षा के प्रयोजनार्थ जांच अवधि अप्रैल, 2008 से सितंबर, 2009 (18 माह) की है। तथापि, क्षति विश्लेषण में वर्ष 2005-06, 2006-07, 2007-08 तथा जांच अवधि शामिल होगी।
- (xiii) डी जी सी आई एंड एस से पिछले तीन वर्षों और जांच अवधि के लिए संबद्ध वस्तु के आयातों के ब्यौरे प्रदान करने का अनुरोध किया गया था। डी जी सी आई एंड एस से अब आंकड़े प्राप्त हो गए हैं और उन पर इस जांच परिणाम में उचित ढंग से विश्वास किया गया है।
- (xiv) प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के परिसरों में सत्यापन किया।
- (xv) हितबद्ध पक्षकारों की मौखिक सुनवाई करने के लिए प्राधिकारी ने 9.2.2010 को सार्वजनिक सुनवाई आयोजित की। सार्वजनिक सुनवाई में भाग लेने वाले पक्षकारों से मौखिक रूप से व्यक्त विचारों के लिखित अनुरोध दायर करने का आग्रह किया गया था।
- (xvi) *** यह चिन्ह इस जांच परिणाम में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना का द्योतक है और प्राधिकारी ने इसे नियमानुसार गोपनीय ही माना है।
- (xvii) उपर्युक्त नियमावली के नियम 16 के अनुसार प्राधिकारी ने ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को उचित सूचना देते हुए 21 जुलाई, 2010 को इन जांच परिणामों के लिए विचारित आवश्यक तथ्यों का प्रकटन किया और उस पर प्राप्त टिप्पणियों पर इस जांच परिणाम में उचित स्थानों पर विचार किया गया है।

2. सार्वजनिक सुनवाई के बाद किए गए अनुरोध :-

टी सी एल द्वारा - टी सी एल के अनुरोध संक्षेप में निम्नानुसार हैं:

- i. टी सी एल ने उत्पादन में कमी की है परंतु उत्पादन कभी बंद नहीं किया है। कंपनी द्वारा उत्पाद का उत्पादन जारी है।
- ii. भारत में संबद्ध उत्पाद के दो उत्पादक अर्थात् टी सी एल तथा मैसूर पेट्रोकेमिकल्स (एम पी एल) हैं जिनके उत्पादन का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	उत्पादन			कुल उत्पादन में टी सी एल %
	टी सी एल	एमपीसीएल	कुल	
2005-06	***	***	***	81.0%
2006-07	***	***	***	79.8%
2007-08	***	***	***	43.3%
2008-09	***	***	***	22.7%
जांच अवधि	***	***	***	19.6%
जांच अवधि- वार्षिकीकृत	***	***	***	19.6%

- iii. टी सी एल ने संबद्ध वस्तु का आयात किया है तथापि, आयात के कारण उनसे अत्यंत भिन्न हैं जिनके बारे में अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है। घरेलू उद्योग की वस्तु और आयातों की कीमत में भारी अंतर है। कच्ची सामग्री (बेंजीन) की वैश्विक कीमतों में वृद्धि होने के बावजूद आयात कीमत में कभी भी कोई खास परिवर्तन प्रदर्शित नहीं हुआ जिसकी वजह से कंपनी लागत में हुई वृद्धि के अनुरूप अपनी कीमत नहीं बढ़ा सकी और उसके पास आयात करने और ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए उसकी पुनः बिक्री करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। वर्ष 2008-09 के दौरान केवल मलेशिया से हुए आयातों में वृद्धि हुई। इस अवधि से पूर्व टी सी एल द्वारा किए गए आयात का हिस्सा कुल आयातों का केवल 7.22 प्रतिशत था। इस तथ्य कि टी सी एल द्वारा वर्ष 2008-09 से पूर्व उत्पाद का आयात नहीं किया जा रहा था, से स्पष्टतः यह सिद्ध होता है कि टी सी एल ने अपने मलेशियाई संयंत्र से आयात करने की कभी मंशा व्यक्त नहीं की है।
- iv. टी सी एल ने भारतीय संयंत्र में अत्यधिक राशि का निवेश किया है जो मलेशियाई संयंत्र में किए गए निवेश से काफी अधिक है। कोई भी समझदार व्यापारिक कंपनी करोड़ों रूपए के मूल्य की अपनी पूंजी को बेकार पड़े रहने और आयात को चुनने की अनुमति नहीं देगी। मलेशियाई संयंत्र परिसमापन की प्रक्रिया में है, इसलिए परिसमापन की प्रक्रिया से गुजर रहे किसी संयंत्र की सुरक्षा हेतु अपने लाभ प्रदायी उद्यम को बंद करना तर्कसंगत नहीं होगा।

v. टी सी एल ने अपना उत्पादन पुनः शुरू करने का कुछ प्रयास किया था परंतु वह पाटित आयातों के कारण ऐसा नहीं कर सकी और इसलिए उसे अपना संयंत्र बंद करना पड़ा। लगाया गया पाटनरोधी शुल्क नितांत अपर्याप्त है और इससे अक्टूबर, 2006-सितंबर, 2008 में हुई क्षति की भरपाई नहीं हुई है। इस अवधि के दौरान आयात वर्ष 2006-07 में 11416 मी.ट. से अत्यधिक बढ़कर आगे और पाटित कीमत पर वर्ष 2007-08 में 19983 मी.ट. के हो गए हैं।

vi. निर्यातकों के असहयोग से केवल यह संकेत मिलता है कि पाटन का वास्तविक स्तर घरेलू उद्योग के अनुमान से कहीं अधिक है।

vii. घरेलू उद्योग को क्षति संबद्ध वस्तु के आयातों के कारण हुई है जिसकी पुष्टि निम्नलिखित से होती है।

क. आयातों में समग्र रूप में वृद्धि हुई है। 4 वर्ष की अवधि के भीतर आयातों में 97 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

ख. आयातों में तुलनात्मक रूप से वृद्धि हुई है। वर्ष 2005-06 में कुल उत्पादन में पाटित आयातों का हिस्सा 62 प्रतिशत था जो जांच अवधि 2008-09 के दौरान कई गुना बढ़कर 553 प्रतिशत हो गया।

ग. वर्ष 2005-06 में कुल खपत में पाटित आयातों का हिस्सा 40 प्रतिशत था। वर्ष 2008-09 में यह बढ़कर खपत का 49 प्रतिशत हो गया।

घ. उत्पादन लागत में वृद्धि के बावजूद आयातों की पहुंच कीमत वही बनी रही। पाटित आयातों के कारण कीमत में अत्यधिक ह्रास तथा कीमत न्यूनीकरण हुआ है।

ड. जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा घटकर 769 मी.ट. हो गई।

च. वर्ष 2001-02 के दौरान जब कोई पाटित आयात नहीं हुआ था, घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा 96 प्रतिशत था। वर्ष 2007-08 में यह घटकर 5 प्रतिशत हो गया तथा जांच अवधि में आगे और घटकर 1.7 प्रतिशत हो गया।

छ. क्षमता उपयोग वर्ष 2005-06 में 59 प्रतिशत से घटकर जांच अवधि में अत्यंत कम 3 प्रतिशत रह गया।

ज. उत्पादन वर्ष 2005-06 में 10442 मी.ट. से तेजी से घटकर जांच अवधि में 847 मी.ट. हो गया।

झ. टी सी एल के पास आधुनिकतम संयंत्र और मशीनें हैं और उन्होंने उत्पादन में कोई गिरावट दर्ज नहीं की है।

- ट. घरेलू उद्योग ने वर्ष 2005-06 के दौरान लाभ कमाया परंतु उसके बाद के वर्षों में उसे घाटा हुआ।
- ठ. पाटित आयातों के कारण निवेश पर आय में भारी गिरावट आई जो जांच अवधि में घटकर ऋणात्मक 20.49 प्रतिशत हो गई।
- ड. वर्ष 2005-06 के दौरान घरेलू उद्योग ने नकद लाभ कमाया परंतु पाटित आयातों के कारण परवर्ती वर्षों में उसे नकद घाटा हुआ।
- ढ. मालसूची में वर्ष 2006-07 से गिरावट आई क्योंकि उत्पादन और बिक्री की मात्रा काफी कम रही है।
- ण. उत्पादन में गिरावट के कारण रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। तथापि, थैलिक एनहाइड्राइट (पी ए एन) के विनिर्माण हेतु किसी कर्मचारी की छंटनी और पुनः नियुक्त नहीं की गई थी।
- त. जांच अवधि के दौरान प्रति व्यक्ति मजदूरी में गिरावट आई क्योंकि मैलिक एनहाइड्राइट संयंत्र के कर्मचारियों का वेतन दूसरे संयंत्रों को आवंटित कर दिया गया था।
- थ. मांग में कोई विरोधाभास नहीं है क्योंकि इसमें क्षति अवधि और जांच अवधि के दौरान भी वृद्धि होती रही। दूसरी ओर घरेलू बिक्री में गिरावट आई।
- द. स्थापित क्षमता में वृद्धि के बावजूद घरेलू उद्योग की उत्पादन क्षमता बेकार बनी रही। उत्पाद की खपत में 70 प्रतिशत की वृद्धि हुई लेकिन घरेलू उद्योग अभी भी उत्पादन या बिक्री में वृद्धि नहीं कर सका।
- ध. चूंकि लगाई गई पूंजी पर आय नकारात्मक (अर्थात् - 20.5 प्रतिशत) है इसलिए पूंजी या निवेश जुटाने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।
- न. पाटन शुरू होने से पूर्व याचिकाकर्ता लाभकारी कीमत प्राप्त करने की स्थिति में था परंतु वे पाटित कीमतों के कारण अपनी कीमत कम करने के लिए विवश हुए थे।
- प. आयात कीमत इतनी कम है कि वह घरेलू उत्पादन की व्यवहार्य लागत से भी कम प्रतीत होती है जिससे बेतहाशा पाटन का पता चलता है।
- फ. वास्तविक क्षति तथा क्षति के खतरे के अलावा, पाटित आयातों के कारण भारत में घरेलू उद्योग के अस्तित्व के लिए भी वास्तविक खतरा उत्पन्न हो गया है। वस्तु के भारी पाटन के परिणामस्वरूप टी सी एल द्वारा संबद्ध वस्तु का उत्पादन कम हुआ है। वस्तुतः पाटन इतनी अधिक मात्रा में हुआ है कि कई प्रयासों के बावजूद भी टी सी एल को अल्प प्रचालन के बाद अपने संयंत्र बंद करने पड़े थे।

ब. घरेलू उद्योग ने वर्ष 2005 में अपनी क्षमता बढ़ाई है परंतु पाटित आयातों के कारण वह इस प्रकार से बढ़ी हुई क्षमता का उपयोग नहीं कर सका। पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वर्ष 2007-08 में अपना उत्पादन घटाना पड़ा। वस्तुतः क्षमता उपयोग वर्ष 2007-08 में इतना कम रहा था कि घरेलू उद्योग भारत में पाटित आयात की शुरुआत से पूर्व विद्यमान क्षमता का उपयोग नहीं कर सका। पाटित आयातों से घरेलू उद्योग अपने उत्पाद का वाणिज्यीकरण करने से वंचित हुआ।

vii. घरेलू उद्योग को क्षति पाटित आयातों के कारण हुई है। मलेशिया और कोरिया से आयातों में वृद्धि हुई है क्योंकि घरेलू उद्योग संबद्ध देशों से पाटित वस्तु की बड़ी मात्रा में हुए आयातों के कारण बंद पड़ा रहा। तथापि, अप्रैल, 2009, जुलाई, 2009 तथा अगस्त 2009 को छोड़कर सभी महीनों के दौरान चीन से प्रति मी.ट. औसत कीमत मलेशिया में प्रति मी.ट. औसत कीमत से काफी कम रही। पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति असंबद्ध देशों से हुए आयातों में वृद्धि होने का कारण है।

क. मांग में कमी : उत्पाद की मांग में लगातार वृद्धि हुई है अतः मांग में कमी घरेलू उद्योग को प्रभावित होने वाला कारक नहीं है।

ख. खपत की पद्धति: खपत की पद्धति में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है।

ग. प्रौद्योगिकी विकास: प्रौद्योगिकी में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है।

घ. प्रतिस्पर्धा की स्थितियां : भारत में कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक व्यवहार अथवा प्रतिस्पर्धारोधी व्यवहार प्रचलित नहीं है।

ड. घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन: निर्यात निष्पादन के कारण घरेलू उद्योग की वित्तीय या आर्थिक स्थिति प्रभावित नहीं हुई है। क्षति निर्धारण के प्रयोजनार्थ निर्यात से संबंधित आंकड़ों को पूर्ववर्ती पैराग्राफ से हटा दिया गया है।

3. मै. मैसूर पेट्रोकेमिकल्स लि. (एम पी एल) के अनुरोध - एम पी एल ने टी सी एल द्वारा दायर पाटनरोधी शुल्क में वृद्धि करने के अनुरोध का समर्थन किया है। तथापि, कंपनी ने वर्तमान जांच से संगत कोई सूचना प्रदान नहीं की है। एम पी एल ने प्रतिपक्षीय हितबद्ध पक्षकारों के इस दावे का खंडन नहीं किया है कि विचाराधीन उत्पाद एम पी एल के लिए एक सह-उत्पाद है और एम पी एल को आयातों से वास्तविक क्षति नहीं हो सकती है।

4. एसोसिएशनों के अनुरोध

4.1 मै. पालिएस्टर रेजिन मैन्यु एसो.-

- क. निर्धारित समय सीमा के भीतर अपेक्षित आंकड़े प्रस्तुत न किए जाने के कारण पाटन का कोई साक्ष्य नहीं - टी सी एल घरेलू उद्योग के सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत, पहुंच मूल्य और क्षति रहित कीमत में परिवर्तन के बारे में कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रही। अतः पाटन के साक्ष्य के अभाव में वर्तमान समीक्षा को तुरंत बंद कर दिया जाना चाहिए।
- ख. घरेलू उद्योग के बारे में सूचना के अभाव में कोई पाटन होने या क्षति विश्लेषण का प्रश्न नहीं उठता। पाटनरोधी शुल्क को जारी रखे जाने से टी सी एल के अंतिम उत्पाद की कीमत तथा बाजारी प्रतिस्पर्धात्मकता पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा।
- ग. मूल जांच के बाद टी सी एल के उत्पादन में 94 प्रतिशत की गिरावट आई। इसके अलावा, उनकी 36वीं वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2008-09 के अधिकांश भाग में उसका संयंत्र ने प्रचालन नहीं किया। अनुषंगी प्रयोक्ता उद्योग के पास उत्पादन में कमी के मद्देनजर आयात करने के अलावा, कोई विकल्प नहीं था।
- घ. संबद्ध वस्तु के नगण्य घरेलू उत्पादन के कारण टी सी एल को "क्षति" होने का प्रश्न नहीं उठता।
- ङ. मैलिक एनहाइड्राइड थैलिक एनहाइड्राइड का एक सह उत्पाद है। पूर्ववर्ती सार्वजनिक सुनवाई के दौरान मैसूर पेट्रोकेमिकल्स लि. (वर्तमान जांच में समर्थक) ने यह स्वीकार किया है कि मैलिक एनहाइड्राइड थैलिक एनहाइड्राइड का एक सह उत्पाद है।
- च. कारणात्मक संबंध स्थापित न होने की वजह से समीक्षा समाप्त कर दी जानी चाहिए। पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बावजूद घरेलू उत्पादन इस आधार पर बंद किया गया था कि बेंजीन की कीमतें असामान्य रूप से अधिक हैं। इस दावे पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि बेंजीन की कीमत में विश्वव्यापी वृद्धि हुई थी।
- छ. क्षति स्वोद्भूत है। मांग में वृद्धि के साथ-साथ बाजार का विस्तार हुआ है परंतु समीक्षा अवधि के दौरान मांग में वृद्धि की तुलना में टी सी एल का घरेलू उत्पादन और बिक्री दोनों कम रही हैं।
- ज. उत्पादन में भारी गिरावट केवल मलेशिया से संबद्ध वस्तु के आयात के कारण आई है। पाटनरोधी-शुल्क लगाए जाने के बाद मलेशिया से हुए आयातों में भारी वृद्धि हुई थी। जांच अवधि के दौरान मलेशिया से हुए आयातों तथा घरेलू उत्पादक, दोनों के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है।

झ. यद्यपि, उत्पाद का कोई घरेलू उत्पादन नहीं हुआ, चीन और इंडोनेशिया पर पाटनरोधी शुल्क लागू है। मलेशिया से होने वाले आयातों पर टी सी एल का नियंत्रण है। इस प्रकार टी सी एल ने एकाधिकार बना लिया है। टी सी एल को क्षति मुख्यतः इसके अपने संयंत्र से हुए संबद्ध वस्तु के आयातों के कारण हुई है।

ट. इस बात को देखते हुए कि मूल जांच में हितबद्ध निर्यातक याबांग का गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के मुद्दे से संबंधित एक मामला सेस्टेट में पहले से ही लंबित है। यह इस जांच में सहयोग नहीं कर रहा है।

4.2 प्लास्टीसाइजर्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन द्वारा किए गए अनुरोध -

- i. किसी भी घरेलू विनिर्माता ने उपर्युक्त अवधियों के लिए आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए हैं।
- ii. टी सी एल द्वारा अगस्त, 2009 से उत्पाद का आयात किया जा रहा है और वह भी भारी मात्रा में। मैलिक एनहाइड्राइड का आयात उनकी सहयोगी कंपनियों अर्थात् बी एम जी कैमिकल प्रा.लि. के जरिए 1260 टन की मात्रा तक किया गया है। टी सी एल तथा बी एम जी कैमिकल्स द्वारा भारत में अन्य पत्तनों से भी एम ए एन का आयात किया जा रहा है। रेन्सन प्रा.लि., सिंगापुर द्वारा भारत को टी सी एल, मलेशियाई संयुक्त उद्यम के एम ए एन का निर्यात किया जा रहा है। टी सी एल विचाराधीन उत्पाद का प्रमुख आयातक है और वह घरेलू उद्योग की प्रात्र नहीं है।
- iii. टी सी एल के अधिवक्ताओं ने यह उल्लेख किया है कि टी सी एल का एम ए एन अव्यवहार्य प्रौद्योगिकी बेंजीन पर आधारित है। इसकी वजह से वे वर्ष 2007 से एम ए एन का उत्पादन बंद करने के लिए बाध्य हुए हैं। आबद्ध जरूरत की पूर्ति हेतु टी सी एल ने उत्पाद का आयात किया क्योंकि यह उत्पादन की तुलना में अधिक किफायती और व्यवहार्य था।
- iv. टी सी एल ने वर्ष 2008 से बुटेन आधारित एम ए एन के विनिर्माण हेतु मलेशिया में एक संयुक्त उद्यम स्थापित किया है। यह बात समझ में नहीं आती है कि भारत में उसी प्रौद्योगिकी का कार्यान्वयन क्यों नहीं किया गया। यदि ऐसा किया गया होता तो भारतीय इकाई की अव्यवहार्यता का प्रश्न ही नहीं उठता।
- v. भारतीय उपभोक्ता उद्योग की लागत पर मलेशियाई संयुक्त उद्यम की सुरक्षा करने और उसे अनुचित लाभ प्रदान करने की टी सी एल की मंशा दुर्भावनापूर्ण है। उनकी सौदा कीमत बातिल एवं शून्य है क्योंकि यह उसकी सहायक कंपनी है।

- vi. विनिर्माता पाटनरोधी कार्यवाही में नहीं आते हैं अपितु, रक्षोपाय के अधीन आते हैं । टी सी एल को उद्योग के सकारात्मक समायोजन को सुकर बनाने के लिए विस्तृत ढांचागत योजना तथा घरेलू उद्योग को हुई क्षति/बाजार विकृति को दूर करने के लिए जरूरी समयावधि का ब्यौरा प्रस्तुत करना चाहिए ।
- vii. आरंभिक शुल्क तथा समीक्षा का उद्देश्य मलेशिया स्थित संयुक्त उद्यम को सुरक्षा प्रदान करना है । दिखाई गई खरीदें मलेशिया संयंत्र से किए गए आयात हैं । इसके अलावा, एम पी एल को एम ए एन के विनिर्माता के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता क्योंकि वे थैलिक एनहाइड्राइड के उत्पादन के दौरान सह उत्पाद के रूप में एम ए एन प्राप्त करते हैं ।
- viii. टी सी एल अत्यधिक लाभ कमाने वाली कंपनी है जो अपने शेयरधारकों को उच्च लाभांश प्रदान कर रही है । दिनांक 31.3.2010 को समाप्त लेखा परीक्षित रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2008-09 के दौरान 4600 लाख रूपए के घाटे की तुलना में टी सी एल का निवल लाभ 2585 लाख रूपए का रहा है । इस समय स्थानीय उद्योग को कोई क्षति नहीं हो रही है ।
- ix. दिनांक 31.3.2010 को समाप्त तिमाही के लिए टी सी एल की लेखापरीक्षित वित्तीय रिपोर्ट के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय, मुंबई ने कंपनी की आरक्षित निधि में टी सी एल इंडस्ट्रीज (मलेशिया) एस डी एन बी एच डी (टी सी एल एम) के साधारण शेयरों में किए गए लगभग 183 लाख रूपए के निवेश की राशि को अवलिखित करने को अनुमोदित किया है । टी सी एल मलेशियाई संयुक्त उद्यम को हुए घाटे को भारत में टी सी एल द्वारा अवलिखित किया जा रहा है । इससे टी सी एल/स्थानीय उद्योग को कोई क्षति न होने की पुनः पुष्टि होती है । टी सी एल ने अग्रिमों/देनदारों की वजह से टी सी एल इंडस्ट्रीज (मलेशिया) एस डी एन बी एच डी में 3769 लाख रूपए का प्रकटन किया है जिसकी वसूली भविष्य में की जा सकती है ।
- x. विश्व में सबसे बड़े उत्पादकों में से एक उत्पादक होने के कारण टी सी एल को सरकार से आयातों के खिलाफ किसी संरक्षण की जरूरत नहीं है और उसने निर्यात पुरस्कार जीते हैं और इसलिए वह अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धा कर सकती है ।
- xi. भारत की मैलिक एनहाइड्राइड की जरूरत प्रति वर्ष 30,000 टन से अधिक है और आयात अनिवार्य हैं ।

xii. एम ए एन का उपयोग मेलेट्स के उत्पादन में किया जाता है । पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से मेलेट्स के आयात होंगे जिससे स्थानीय उद्योग बंद हो सकता है तथा व्यापक बेरोजगारी फैल सकती है । मेलेट्स के स्थान पर घरेलू रूप से उत्पादित एक्रिलेट्स, विनायल एसीटेट्स कोपॉलीमर आदि का प्रयोग किया जा सकता है और इससे मेलेट्स उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है ।

5. सांक्षी रिजेट वर्क्स, चीन जन.गण. की ओर से निर्यातक मै. डी डी इंटरनेशनल द्वारा किए गए अनुरोध ।

i) वर्ष 2008 की तुलना में वर्ष 2009 में एम ए एन की कच्ची सामग्री कीमत में भारी परिवर्तन हुआ है ।

ii) पाटनरोधी शुल्क से निर्यातों को भारी धक्का लगा है ।

iii) भारत में कोई घरेलू विनिर्माता नहीं है ।

iv) टी सी एल ने मलेशिया में एम ए विनिर्माण सुविधा स्थापित की है ।

v) मलेशिया स्थिति टी सी एल का कारखाना एक बार बंद हो जाने पर वह भारत में एम ए की मांग को पूरा नहीं कर सकती ।

6. आयातकों की ओर से किए गए अनुरोध;

आयातकों अर्थात् मै. जयदीप एजेंसीज, मेकेम्को रेजिन्स प्रा लि., रचना प्लास्टीसाइजर्स, के एल जे. सिल्वासा प्लास्ट, वीसेन इंडस्ट्रीज ने जांच अवधि के दौरान पूर्ववर्ती दो वर्षों में किए गए आयातों के बारे में सूचना प्रदान की है जो निम्नानुसार है:

मात्रा मी.ट. में

आयातकों का नाम	2006-07	2007-08	जांच अवधि
जयदीप एजेंसी	***	***	***
मेकेम्को	***	***	***
रचना प्लास्टीसाइजर्स	***	***	***
के एल जे सिल्वासा	***	***	***
वीसेन	***	***	***
कुल	1116.5	2593.1	2687.7

इस अवधि के दौरान संबद्ध देशों अर्थात् चीन जन.गण., इंडोनेशिया और चीनी ताइपेई से हुए आयात निम्नानुसार रहे हैं:

मात्रा मी.ट. में

आयातकों का नाम	2006-07	2007-08	POI
जयदीप एजेंसी	***	***	***
मैचमको	***	***	***
रन्चा प्लास्टीसाइजर्स	***	***	***
के एल जे सिल्वासा	***	***	***
वीसेन	***	***	***
कुल	1116.5	2353.1	1568.7

यह अनुरोध किया गया है कि अधिकांश आयात अग्रिम लाइसेंस पर किए जाते हैं। इसके अलावा, आयात का स्रोत संबद्ध देश से बदलकर अन्य देश अर्थात् कोरिया, मलेशिया, सिंगापुर हो गया है। इस अवधि के दौरान चीन से हुए आयातों में भी अत्यधिक गिरावट आई है। चीन से उपर्युक्त आयातकों द्वारा किए गए आयात कुल मिलाकर वर्ष 2006-07 में 1116.5 मी.ट., 2007-08 में 2353.1 मी.ट. तथा जांच अवधि में 1472.75 मी.ट. के हुए हैं जो वार्षिक आधार पर 981 मी.ट. बनते हैं।

7. सार्वजनिक सुनवाई के बाद लिखित अनुरोधों के उत्तर

(क) भारतीय रसायन परिषद द्वारा

घरेलू उद्योग की सुरक्षा हेतु शुल्क अपर्याप्त था क्योंकि पर्याप्त संरक्षण प्रदान करने के लिए जरूरी शुल्क का यह मात्र एक अंश था। इस बात पर खास तौर पर विचार करते हुए कि भारी मात्रा में पाटन उन 11 महीनों की अवधि के दौरान हुआ जब जांच चल रही थी। पाटनरोधी शुल्क की गणना करते समय इस अवधि के तथ्यों पर विचार नहीं किया गया था। परिणामतः भारत में एममात्र प्रमुख मैलिक एनहाइड्राइड के उत्पादक को दो वर्ष तक संयंत्र निष्क्रिय रखना पड़ा था। आई सी सी ने स्थिति की समीक्षा की है और आवेदक की अपेक्षानुसार पाटन से पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने की सिफारिश की है ताकि घरेलू उद्योग प्रचालन कर सके।

(ख) पोलिस्टर रीजन मैनु. एसो.

(i) भारत भर में फैले 100 से अधिक यू पी रीजन विनिर्माता हैं । लगभग सभी रीजन विनिर्माता लघु उद्योग क्षेत्र (अब एस एम ई) में हैं जो 5000 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान कर रहे हैं । इन रीजनों का उपयोग फाइबर ग्लास रीइन्फोर्सड प्लास्टिक्स (एफ आर पी) के विनिर्माण में प्रमुख कच्ची सामग्री के रूप में किया जाता है । हमारे देश में 2000 से अधिक एफ आर पी विनिर्माता हैं जो 500000 से अधिक लोगों को रोजगार दे रहे हैं ।

(ii) हमारे देश में यू पी आर का वर्तमान उत्पादन 180000 टी पी ए का है जिसमें 20000 टन से अधिक मैलिक एनहाइड्राइड का उपयोग किया जाता है । मैलिक एनहाइड्राइड अनसैचुरेटेड पॉलिस्टर रीजनों के विनिर्माण हेतु एक प्रमुख कच्ची सामग्री है । हमारे देश में मैलिक एनहाइड्राइड की कुल खपत अनुमानतः 40000 टी पी ए है ।

(iii) हमारे देश में इस समय मैलिक एनहाइड्राइड का कोई उत्पादन नहीं होता है और समूची जरूरत की पूर्ति आयातों के जरिए होती है ।

(iv) पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद मै. तिरूमलाई कैमिकल्स ने न केवल उत्पादन लगभग 12,000 टी पी ए रखने अपितु उसे बढ़ाकर 18000 एम टी ए करने का वादा किया था ताकि घरेलू बाजार की मांग को आंशिक रूप से पूरा किया जा सके । इसके बजाए उन्होंने पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बाद अपना संयंत्र पूर्णतः बंद कर दिया और मलेशिया स्थिति अपने संयंत्र से आपूर्ति शुरू कर दी जिस पर कोई पाटनरोधी शुल्क लागू नहीं था ।

(v) पी सी एल मलेशिया ने यह उत्पाद अपनी व्यापार शाखा रैनसन पी पी ई लि., सिंगापुर के जरिए भेजा और आगे भारत में अपने एजेंट बी एम जी. कैमिकल्स प्रा.लि. के जरिए । इस प्रकार उनका भारतीय बाजार में लगभग एकाधिकार है ।

(vi) जिन अन्य उत्पादकों पर पाटनरोधी शुल्क लागू था, उन्होंने भारतीय बाजार में अपनी रुचि इस हद तक खत्म कर दी कि कई बार उन्होंने कीमतें उद्धृत करने से मना कर दिया है । तथापि, वे पड़ोसी देशों और मध्यपूर्व के अनसैचुरेटेड पॉलिस्टर रेजिन उत्पादकों को

सामग्री की आपूर्ति कर रहे हैं। इस प्रकार उत्पादकों को लागत लाभ प्राप्त है और वे भारतीय बाजार में सामग्री की आसानी से बिक्री कर सकते हैं जैसा कि पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बाद यू पी आर के बढ़े हुए आयातों से देखा जा सकता है। यदि यह स्थिति बनी रहती है तो इसका यू पी आर के घरेलू उत्पादकों पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है और वे संयंत्र बंद करने के लिए बाध्य हो सकते हैं।

(vii) हमारा मानना है कि मै. पी सी एल ने सरकार को उचित ढंग से अभ्यावेदन नहीं दिया है और ऐसा प्रतीत होता है कि भारत में अपना संयंत्र शुरू करने की उनकी कोई मंशा नहीं है, अपितु इसके बजाए वे संरक्षण चाहते हैं ताकि उनके मलेशियाई विनिर्माण प्रचालनों को सुविधा और सहायता मिल सके।

(ग) घरेलू उद्योग द्वारा :

क. पालिएस्टर रेजिन मैनु. एसो. (पी आर एम ए) द्वारा दायर लिखित अनुरोध के संबंध में

(i) संदर्भ पैरा 4 से 8 : पी आर एम ए ने इस आशय का अत्यंत साधारण वक्तव्य दिया है कि टी सी एल ने परिस्थितियों में ऐसे किसी परिवर्तन के बारे में कोई साक्ष्य और सूचना प्रस्तुत नहीं की है, जिससे लागू शुल्क की समीक्षा की जा सके जिसमें सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत, पहुंच कीमत और घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत जैसे कारक शामिल हैं। यह अनुरोध किया गया है कि टी सी एल ने 1 सितंबर, 2009 के अपने पत्र द्वारा परिस्थितियों में परिवर्तन के बारे में विस्तृत सूचना प्रस्तुत की है।

(ii) संदर्भ पैरा 9 से 11 : पी आर एम ए ने अपने इस तर्क के समर्थन में कि संबद्ध वस्तु के नगण्य घरेलू उत्पादन के कारण घरेलू उत्पादक को "क्षति" का कोई प्रश्न नहीं उठता, प्राधिकारी के कुछेक निर्णयों को उद्धृत किया है अर्थात् यूरोपीय संघ, अमरीका, चीन जनगण तथा ब्राजील के मूल के या वहां से निर्यातित एथेलिन-प्रोपेलीन-नान-कन्ज्यूगेटेड-डाइन-मोनोमर (ई पी डी एम) रबड़ के आयातों से संबंधित मामले में मध्यावधि पाटनरोधी समीक्षा जांच और सउदी बेसिक इंड. व अन्य बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी ने डी जी ए डी द्वारा जारी 6 अगस्त, 2009 के अंतिम जांच परिणाम, वित्त मंत्रालय, 2006 ई सी आर 106 (न्याया-दिल्ली)

(iii) यह अनुरोध किया जाता है कि पी आर एम ए ने अपनी जरूरत के अनुसार निर्णयों के एक सीमित भाग का उल्लेख किया है। यदि इन निर्णयों पर उचित विचार किया जाए तो यह सिद्ध किया जा सकता है कि उपर्युक्त निर्णय वर्तमान जांच पर लागू नहीं होते हैं।

(iv) उपर्युक्त दोनों मामलों में घरेलू उद्योग ने उत्पादन बंद कर दिया है और उनके द्वारा उत्पादन पुनः शुरू किए जाने की कोई मंशा नहीं है। तथापि, वर्तमान जांच में ऐसा नहीं है। घरेलू उद्योग ने उत्पादन बंद नहीं किया है। वस्तुतः टी सी एल ने उत्पादन पुनः शुरू करने के कई प्रयास किए थे परंतु वह पाटित आयातों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सका और संक्षिप्त परिचालन के बाद संयंत्र बंद करना पड़ा। यह भी नोट किया जाना चाहिए कि टी सी एल की मंशा अपने निवेश का लाभ उठाने के लिए अपना उत्पादन शुरू करने की है।

(v) इसके अलावा, अपना उत्पादन पुनः शुरू करने की घरेलू उद्योग की मंशा की पुष्टि इस तथ्य से भी की जाती है कि टी सी एल संयंत्र का रखरखाव चालू स्थिति में किया जा रहा है और समस्त कर्मचारी अभी भी कंपनी की पंजी पर हैं एवं संयंत्र तथा मशीनरी निष्क्रिय पड़ी हुई है। परंतु उत्पादन अल्प अवधि के लिए किया गया है। टी सी एल की मंशा संयंत्र एवं मशीनरी का निपटान करने या उत्पादन बंद करने की नहीं है। यह केवल अस्थायी बाजारी धक्का है कि टी सी एल एम ए एन का उत्पादन नहीं कर सकती। भारतीय बाजार में उथल-पुथल लाने वाले पाटित आयातों के खिलाफ पर्याप्त पाटनरोधी शुल्क के रूप में भारत सरकार की अल्प सहायता से टी सी एल अत्यंत कम समय में व्यापार करना शुरू कर देगी।

(vi) संदर्भ पैरा 12 : थैलिक एनहाइड्राइड की उत्पादन प्रक्रिया में सह उत्पाद के रूप में मैलिक एनहाइड्राइड (एम एन एन) या फ्यूमैरिक एसिड प्राप्त किया जा सकता है। यद्यपि, मैसूर कैमिकल्स लि. द्वारा थैलिक एनहाइड्राइड की उत्पादन प्रक्रिया में एम ए एन का उत्पादन का किया जाता है तथापि, टी सी एल थैलिक एनहाइड्राइड की उत्पादन प्रक्रिया में सह उत्पाद के रूप में फ्यूमैरिक एसिड का उत्पादन करती है। अनुरोध है कि टी सी एल ने थैलिक की उत्पादन प्रक्रिया में सह उत्पाद के रूप में एम ए एन प्राप्त नहीं किया है।

(vii) एनहाइड्राइड : टी सी एल ने एम ए एन के उत्पादन हेतु अलग से एक संयंत्र स्थापित किया है और इसका सत्यापन प्राधिकारी कर सकते हैं। हम अपने कारखाना परिसरों में एम ए एन संयंत्रों की मौजूदगी का सत्यापन करने के लिए प्राधिकारी को आमंत्रित करते हैं।

(viii) संदर्भ पैरा 13 से 22 : पी आर एम ए ने यह तर्क दिया है कि कारणात्मक संबंध के स्थापित न होने के कारण समीक्षा समाप्त की जानी चाहिए क्योंकि टी सी एल ने मलेशिया स्थित अपने संयंत्र से आयातों की राह आसान करने हेतु समीक्षा अवधि के दौरान उत्पादन बंद कर दिया है। भारतीय संयंत्र में

टी सी एल का निवेश टी सी एल मलेशिया में किए गए निवेश से कहीं अधिक है । इसके अलावा, टी सी एल मलेशिया, परिसमापन की प्रक्रिया से गुजर रही है अतः इस बात पर विचार करना अत्यंत निराधार और अतार्किक है कि घरेलू उद्योग पहले से ही परिसमापन की प्रक्रिया से गुजर रही कंपनी को संरक्षण प्रदान करने के लिए अपने लाभप्रदायी उद्यम को बंद कर देगा ।

(ix) तथापि, चूंकि मलेशियाई कंपनी स्वयं परिसमापन की प्रक्रिया से गुजर रही है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि हमने मलेशियाई संयंत्र से वस्तु का आयात करने मात्र के लिए भारतीय संयंत्र में उत्पादन बंद कर दिया था । यद्यपि, मलेशियाई संयंत्र बेहतर और अधिक कारगर फीड स्टॉक का उपयोग करता है, तथापि, भारत में उत्पादन बंद करना और मलेशियाई उत्पादन पर भरोसा करना समझदारी नहीं है क्योंकि कंपनी पहले से ही परिसमापन के अधीन है । अतः उनके इस तर्क में कोई दम नहीं है कि पी सी एल ने केवल अपने मलेशियाई संयंत्र से आयात करने के लिए भारतीय संयंत्र को बंद किया है ।

(x) श्री पैरा 23 : पी आर एम ए ने कुछेक अपुष्टिकृत आरोप लगाए हैं जबकि तथ्यों से अन्यथा पता चलता है । यदि संबद्ध देशों के आपूर्तिकर्ता ने भारतीय ग्राहकों को वस्तु का निर्यात करने से मना किया होता तो आयात की मात्रा में गिरावट आई होती । इसके विपरीत, पिछले चार वर्षों में आयात मात्रा में 97 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है अतः उनके तर्क में कोई दम नहीं है ।

ख. इंडियन प्लास्टीसाइजर्स मैनु एसो. (आई पी एम ए) द्वारा दायर लिखित अनुरोध के संबंध में

i. टी सी एल द्वारा आयात : टी सी एल ने मलेशिया स्थित अपनी संबद्ध कंपनी से भारी मात्रा में आयात किया है और एक आयातक होने के नाते यह घरेलू उद्योग की पात्र नहीं है और इसे नियम 2(ख) के प्रयोजनार्थ अपात्र घरेलू उत्पादक घोषित किया जाना चाहिए । जहां तक मलेशिया से संबद्ध उत्पाद के आयात का संबंध है, घरेलू उद्योग का अनुरोध है कि मलेशिया संबद्ध देश नहीं है । चूंकि मलेशिया संबद्ध देश नहीं है, इसलिए नियम 2 (ख) के अंतर्गत उपबध्ति अपवर्जन खंड लागू नहीं होता है । इस बात को ध्यान में रखते हुए मलेशिया से हुए आयातों का इस जांच के परिणाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

ii. बेंजीन बनाम बूटेन संयंत्र : आई पी एम ए ने यह दावा किया है कि हमने बेंजीन प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल द्वारा एम ए एन के अव्यवहार्य विनिर्माण का जो उल्लेख किया है, वह गलत है । हमने यह बताया है कि यद्यपि बेंजीन की

कीमत में वृद्धि हुई है तथापि, एम ए एन का पहुंच मूल्य नहीं बढ़ा है, इससे घरेलू उद्योग अपनी उत्पादन लागत में बढ़ोत्तरी के अनुरूप एम ए एन की कीमत को बढ़ाने से वंचित हुआ है ।

iii. इसके अलावा, मूल जांच में एम ए एन के उत्पादन में बेंजीन बनाम बूटेन के उपयोग का मुद्दा भी उठाया गया है । मूल जांच में यह माना गया था कि चूंकि निर्यातक स्वयं बेंजीन का उपयोग करते हैं, इसलिए वे ये दावा नहीं कर सकते कि भारतीय घरेलू उत्पादक को बेंजीन का उपयोग नहीं करना चाहिए । वर्तमान जांच में किसी भी निर्यातक ने सहयोग नहीं किया है अथवा ऐसी कोई सूचना प्रदान नहीं की है जिससे यह सिद्ध होता हो, कि वे एम ए एन के उत्पादन के लिए बूटेन का उपयोग कर रहे हैं । जब निर्यातक और घरेलू उद्योग दोनों एक ही प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर रहे हैं तो बूटेन के उपयोग का प्रश्न ही नहीं उठता ।

iv. टी सी एल का टी सी एल एम में अपने संयुक्त उद्यम में अत्यंत कम दावा है । संबद्ध कंपनी—टी सी एल एम में कम दावे का अर्थ यह नहीं है कि टी सी एल को भी मलेशियाई कंपनी द्वारा प्रयुक्त प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना चाहिए ।

v. टी सी एल एम से आयात : आई पी एम ए ने दावा किया है कि टी सी एल ने भारतीय उपभोक्ता उद्योग की लागत पर मलेशियाई संयुक्त उद्यम का संरक्षण करने और उसे अनुचित लाभ प्रदान करने की जो दुराशयपूर्ण मंशा प्रकट की है, अस्वीकार्य है । पूर्ववर्ती पैराग्राफों में किए गए अनुरोधों के अलावा, यह अनुरोध किया जाना चाहिए कि मलेशियाई जे वी कोई नया उद्यम नहीं है । यह 14 से अधिक वर्षों से प्रचालनरत है । इन सभी वर्षों के दौरान टी सी एल मलेशिया से संबद्ध उत्पाद के नगण्य या छिटपुट आयातों के साथ संबद्ध उत्पाद का विनिर्माण कर रही है । यह अनुरोध किया जाता है कि टी सी एल से हुए आयातों में केवल 2008-09 के दौरान वृद्धि हुई है । परंतु मलेशिया से संबद्ध उत्पाद के आयात का कारण संबद्ध देशों से एम ए एन का सतत पाटन है न कि आई पी एम ए का अनुमान ।

vi. आई पी एम ए का दावा है कि घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है क्योंकि उनके लाभ में वृद्धि हुई है । यह नोट किया जाना चाहिए कि समग्र रूप में कंपनी के लाभ में वृद्धि हुई है क्योंकि थैलिक एनहाइडाइड, फ्यूमेरिक एसिड तथा अन्य खाद्य एसिड जैसे अन्य उत्पादों से संबंधित प्रचालन में वृद्धि हुई है । चूंकि मध्यावधिक उत्पादन को छोड़कर एम ए एन संयंत्र बंद कर दिया गया है, इसलिए टी सी एल ने एम ए एन से संबंधित अपने प्रचालनों पर कोई धन नहीं कमाया है ।

vii. इसके अलावा, आई पी एम ए ने यह उल्लेख किया है कि टी सी एल मलेशिया संयुक्त उद्यम को हुए घाटे को टी सी एल इंडिया द्वारा अवलिखित किया जा रहा है और तदनुसार घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है । इस तर्क में वह मूलभूत आधार नहीं है कि पाटनरोधी जांच में क्षति का आकलन कैसे होता है । टी सी एल ने कभी यह दावा नहीं किया है कि उसे मलेशियन जे वी में निवेश के अवलिखित मूल्य के कारण घाटा हो रहा है । इस वजह से हुए घाटे को एम ए एन से संबंधित भारतीय प्रचालनों में हुए घाटे में नहीं जोड़ा गया है । इस मुद्दे का संबंध देशों से हुए पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति से कोई लेना-देना नहीं है ।

viii. टी सी एल एम ने टी सी एल की भागीदारी के लिए कोई प्रावधान अपेक्षित नहीं है : अग्रिमों/देनदारों के कारण टी सी एल एम में पी सी एल की 3769 लाख रुपए की भागीदारी की वसूली की संभावना का तात्पर्य यह नहीं है कि टी सी एल एम के प्रचालन व्यवहार्य हैं । शेयर पूंजी एवं ऋण के रूप में निवेश अलग-अलग हैं । यद्यपि, शेयर पूंजी में निवेश किसी कंपनी की पूंजी का भाग होता है, तथापि, ऋण एवं पूंजी कंपनी की देनदारी होती है । परिसमापन प्रक्रिया के अंतर्गत ऋण एवं अग्रिम के निपटान को मालिक की पूंजी की तुलना में अधिमान प्रदान किया जाता है । टी सी एल की आशा है कि यद्यपि टी सी एल एम के निवल मूल्य में गिरावट आई है, तथापि टी सी एल एम की परिसंपत्तियां उसकी देनदारियों को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं । अतः टी सी एल ने इस हेतु प्रावधान करना आवश्यक नहीं समझा है ।

प्राधिकारी द्वारा जांच :

8. प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऊपर किए गए उल्लेखानुसार मै0 डी डी इंटरनेशनल को छोड़कर संबंध देशों के किसी उत्पादक/निर्यातक ने कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है । इसके अलावा आवेदक घरेलू उद्योग ने उत्पादन बंद कर दिया है और दूसरे घरेलू उत्पादक ने लागत एवं क्षति से संबंधित सूचना प्रदान नहीं की है । इस बात को देखते हुए प्राधिकारी यह मानते हैं कि इस बात का निर्धारण करना

आवश्यक नहीं है कि क्या वर्तमान आयात पाटित कीमतों पर हुए हैं और यदि ऐसा है तो पाटन की मात्रा क्या है क्योंकि प्राधिकारी यह मानते हैं कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति का निर्धारण वर्तमान जांच के लिए प्रासंगिक नहीं है क्योंकि रिकॉर्ड में यह निर्धारित करने की पर्याप्त सूचना है कि क्या भारतीय घरेलू उद्योग को नियम 11 के अर्थ के भीतर क्षति हुई है।

9. मूल जांच और वर्तमान समीक्षा आवेदन में विचाराधीन उत्पाद चीन जन गण, चीनी ताइपेई और इंडोनेशिया के मूल का या वहां से निर्यातित मैलिक एन हाइड्राइड (एम ए एन) है।

10. विचाराधीन उत्पाद "मैलिक एनहाइड्राइड (एम ए एन) है (जिसे संबद्ध वस्तु भी कहा गया है)"। एम ए एन एक कार्बनिक अम्लक एनहाइड्राइड ($C_2H_4O_3$) है जो पिलो आकार के ब्रिकेट रूप में या मोल्टन रूप में सामान्यतः उपलब्ध होता है। दोनों प्रकारों को इस जांच में विचाराधीन उत्पाद के भीतर माना गया है। एम ए एन का उपयोग अनसंचुरेटेड पालिस्टर रेजिन, अल्किट रेजिन, पेपर साइजिंग रसायन, कीटनाशकों तथा परिष्कृत रसायनों जैसे व्यापक उत्पादों के विनिर्माण में किया जाता है। एम ए एन आई टी सी (एच सी) उप शीर्ष 29171400 के अंतर्गत वर्गीकृत है। तथापि, यह सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर किसी भी रूप में बाध्यकारी नहीं है।

11. प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद के मुद्दे के बारे में किसी हितबद्ध पक्षकार ने कोई तर्क नहीं दिया है। अतः प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के उसी क्षेत्र पर विचार किया है जिस पर पूर्व में अधिसूचित अंतिम जांच परिणाम में विचार किया गया था। इसके अलावा, प्राधिकारी का प्रस्ताव यह मानने का है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तु के समान वस्तु है।

12. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए तर्कों के मद्देनजर प्राधिकारी ने विभिन्न लागू सांविधिक उपबंधों की जांच की है। प्राधिकारी ने विभिन्न विधिक उपबंधों के संबध में निम्नानुसार मत व्यक्त किया है:

(क) वर्तमान जांच धारा 9 (5) और नियम 23 के अंतर्गत की जा रही है, जिनमें निम्नानुसार उपबंध है:

नियम 23. समीक्षा. - (1) निर्दिष्ट प्राधिकारी पाटनरोधी शुल्क को सतत रूप से लगाए जाने की जरूरत की समय-समय पर समीक्षा करेंगे और उसे प्राप्त इस आशय की सूचना के आधार पर संतुष्ट होने के उपरांत ऐसे शुल्क को समाप्त किए जाने के लिए केन्द्र सरकार को सिफारिश करेंगे कि इसे सतत रूप से लगाए जाने का कोई औचित्य नहीं है।

(2) उप-नियम (1) के अंतर्गत शुरू की गई कोई समीक्षा ऐसी समीक्षा की शुरुआत की तारीख से 12 माह से अनधिक अवधि के भीतर संपन्न की जाएगी।

(3) नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, तथा 20 के उपबंध समीक्षा के मामले में आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

(ख) यह नोट किया जाता है कि नियम 11 के उपबंध मध्यावधिक समीक्षाओं में भी पूर्णतः लागू होते हैं। नियम 11 में निम्नानुसार उपबंध है :

11. क्षति का निर्धारण: (1) विनिर्दिष्ट देशों से आयातों के मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी आगे इस आशय का एक जांच परिणाम दर्ज करेंगे कि भारत में ऐसी किसी वस्तु के आयात से किसी स्थापित उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है या क्षति होने का खतरा उत्पन्न हो गया है या उससे भारत में किसी उद्योग की स्थापना में वास्तविक बाधा उत्पन्न हुई है।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमत पर उसके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए और इन नियमों के अनुबंध-II में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार घरेलू उद्योग को हुई क्षति, घरेलू उद्योग को क्षति के खतरे, घरेलू उद्योग की स्थापना के लिए वास्तविक बाधा और पाटित आयातों तथा क्षति के बीच कारणात्मक संबंध का निर्धारण किया जाएगा।

(ग) यह देखा जाता है कि प्राधिकारी के लिए घरेलू उद्योग को हुई क्षति का निर्धारण करना अपेक्षित है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग को हुई क्षति के निर्धारण का तरीका नियमावली के नियम 11 और अनुबंध-II में विस्तार से उल्लिखित है।

(घ) नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग को परिभाषित किया गया है और उसमें निम्नानुसार उपबंध है:-

(ख) "घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, परंतु जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक होते हैं तो ऐसे मामले में (ऐसे उत्पादकों) को घरेलू उद्योग का भाग नहीं माना जाएगा।

13. विभिन्न विधिक उपबंधों को ध्यान में रखते हुए यह नोट किया जाता है कि-

(क) प्राधिकारी के लिए वर्तमान मामले में घरेलू उद्योग को हुई क्षति का निर्धारण करना अपेक्षित है। टी सी एल ने भी यह स्वीकार किया है कि वर्तमान मामले में प्राधिकारी के लिए घरेलू उद्योग को हुई क्षति का निर्धारण करना अपेक्षित है। वस्तुतः टी सी एल ने यह दलील दी है कि पाटित आयातों से घरेलू उद्योग को क्षति हुई है। टी सी एल ने यह तर्क

दिया है कि पाटित आयातों से सतत वास्तविक क्षति हुई है और भारत में घरेलू उद्योग की स्थापना में विकृति आ रही है ।

(ख) नियम 11 में "घरेलू उद्योग" के संबंध में क्षति के निर्धारण का उपबंध है । ऐसे घरेलू उद्योग को नियम 2(ख) में ऐसे घरेलू उत्पादकों के रूप में परिभाषित किया गया है जिनका सामूहिक उत्पादन भारतीय उत्पादन में "एक बड़ा अनुपात" बनता हो ।

(ग) पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किए जाने का तर्क देने वाले कुछेक हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि टी सी एल ने मलेशिया से विचाराधीन उत्पाद का भारी मात्रा में आयात किया है । प्राधिकारी इस बात पर विचार करना अनावश्यक मानते हैं कि क्या मलेशिया से टी सी एल द्वारा किए गए आयातों की जांच नियम 2(ख) के अंतर्गत विवेकाधीन अपवर्जन उपबंध के मद्देनजर की जानी चाहिए क्योंकि प्राधिकारी का यह मत है कि उससे वर्तमान निर्धारण में परिवर्तन नहीं होगा ।

(घ) केवल टी सी एल ने वर्तमान जांच में भाग लिया है और यह तर्क दिया है कि केवल टी सी एल से संबंधित सूचना के आधार पर विचाराधीन उत्पाद के आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है । टी सी एल का यह तर्क नहीं है कि पाटित आयातों से अन्य घरेलू उत्पादकों को क्षति हुई है । मैसूर पेट्रोकेमिकल्स लि. (एम पी एल) ने न तो प्राधिकारी को क्षति की कोई सूचना प्रदान की है और न ही यह दावा किया है कि आयातों से एम पी एल को क्षति हुई है ।

(ङ) चूंकि एम पी एल ने प्राधिकारी के साथ सहयोग नहीं किया है और क्षति संबंधी सूचना प्रदान नहीं की है, इसलिए प्राधिकारी इस बात पर विचार करने के लिए बाध्य हुए हैं कि क्या टी सी एल नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग हैं और क्या घरेलू उद्योग को हुई क्षति का निर्धारण केवल टी सी एल द्वारा प्रदत्त सूचना के आधार पर किया जा सकता है । प्राधिकारी यह नोट करने के लिए बाध्य हुए हैं कि टी सी एल को नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर "घरेलू उद्योग" नहीं माना जा सकता क्योंकि टी सी एल का उत्पादन निम्नलिखित तालिका के अनुसार भारतीय उत्पादन का अत्यंत कम 19.6% बनता है :

वर्ष	उत्पादन			कुल उत्पादन में टी सी एल का %
	टीसीएल	एमपीसीएल	कुल	
2005-06	***	***	***	81.0%
2006-07	***	***	***	79.8%

2007-08	***	***	***	43.3%
2008-09	***	***	***	22.7%
जांच अवधि	***	***	***	19.6%
जांच अवधि - वार्षिकीकृत	***	***	***	19.6%

इस प्रकार, टी सी एल का उत्पादन भारतीय उत्पादन का एक बड़ा भाग नहीं बनता है ।

(च) जहां तक टी सी एल के इस तर्क का संबंध है कि पाटन से यह कंपनी उत्पाद का उत्पादन करने और बिक्री करने से वंचित हुई है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह मुद्दा क्षति निर्धारण के लिए प्रासंगिक है न कि घरेलू उद्योग के क्षेत्र के बारे में निर्णय लेने के लिए । घरेलू उद्योग के क्षेत्र को तय करने के लिए केवल भारतीय उत्पादन की मात्रा प्रासंगिक होती है । निर्विवाद तौर पर जांच अवधि के दौरान भारतीय उत्पादन की मात्रा 4310 मी.ट. थी जिसमें से मात्र *** मी.ट. टी सी एल का उत्पादन बनता है, शेष उत्पादन एम पी एल का है ।

(छ) वर्तमान जांच के तथ्यों के अनुसार प्राधिकारी के लिए इस बात पर विचार करना अपेक्षित नहीं है कि क्या खंडित बाजारों से संबंधित नियम 2(ख) का परंतुक वर्तमान मामले में प्रासंगिक है; न ही वर्तमान उद्योग कोई खंडित उद्योग है और इसमें कई उत्पादक शामिल हैं ।

(ज) टी सी एल और एम पी एल समान घरेलू बाजार में प्रचालन कर रही है । निर्विवाद रूप से एम पी एल ने अपना उत्पादन और बाजार हिस्सा लगभग बनाए रखा है जबकि टी सी एल का बाजार हिस्सा घटकर भारत में खपत में मात्र 1.57% हो गया है । इस बात की व्याख्या नहीं की गई है कि एम पी एल किस प्रकार समान बाजारी स्थितियों में अपना उत्पादन और बाजार हिस्सा बनाए रखने में समर्थ रही है ।

(झ) यह स्पष्ट किया जाता है कि वर्तमान समीक्षा पर नियम 5 लागू नहीं होता है । वर्तमान जांच में याचिकाकर्ता के आधार पर गौर करना अपेक्षित नहीं है । तथापि, नियम 11 (जो निर्विवाद तौर पर समीक्षाओं के मामले में लागू होता है) के अंतर्गत घरेलू उद्योग को हुई क्षति और नियम 5 के अंतर्गत आवेदकों का आधार दो विशिष्ट और पृथक अपेक्षाएं हैं ।

14. प्रकटन विवरण पर टिप्पणियाँ

(क) मै. इंडियन प्लास्टीसाइजर्स मैन्यु. एसो. ने अपने पूर्ववर्ती अनुरोध दोहराए हैं और यह बताया है कि मै. भारतीय रसायन परिषद ने पूर्ववर्ती या समीक्षा जांच में इससे पहले पाटनरोधी कार्यवाही में कभी भाग नहीं लिया है परंतु लिखित अनुरोधों पर उत्तर प्रस्तुत किया है। इसके अलावा उनके मलेशिया स्थिति इकाई का परिसमापन को प्रबंधन, वित्तीय अड़चनों और अन्य बाह्य कारकों की वजह से हो सकता है। मिलेट प्लास्टीसाइजर्स, अनसेचुरेटेड पॉलिएस्टर रेजिन का विनिर्माण, एम. ए. एन. के प्रमुख उपभोक्ता लघु क्षेत्र में हैं।

(ख) मै. पॉलिएस्टर रेजिन मैन्यु. एसो. ने अपने पूर्ववर्ती अनुरोध दोहराए हैं और यह अनुरोध किया है कि टी सी एल द्वारा प्रस्तुत जांच की शुरुआत के आधारस्वरूप सूचना असत्य और अपर्याप्त है। इसके अलावा, संबद्ध देशों द्वारा संबद्ध वस्तु के आरोपित पाटित आयातों और घरेलू उद्योग को हुई आरोपित क्षति के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ता के भारतीय प्रचालनों में क्षति अवधि के दौरान भारी गिरवट आई है ताकि मलेशिया और सिंगोपुर से आयात किए जा सकें। चूंकि कोई घरेलू उद्योग नहीं है, इसलिए किसी पाटन या क्षति के विश्लेषण का प्रश्न नहीं उठता। संबद्ध वस्तु पर पाटनरोधी शुल्क को निरंतर लगाए जाने का अंतिम उत्पादों की कीमत पर दूरगामी प्रभाव पड़ा है और उससे अंतिम उत्पादों के घरेलू विनिर्माताओं की प्रतिस्पर्धात्मकता प्रभावित हुई है।

(ग) मै. तिरुमलाई कैमिकल्स लि. (टी सी एल)

I. यह अनुरोध किया गया है कि घरेलू उद्योग की संरचना के बारे में प्राधिकारी के विवरण एक-दूसरे के प्रतिकूल हैं। एक ओर प्राधिकारी इस बात पर सहमत हैं कि किसी समीक्षा जांच में नियम 5 के अंतर्गत परिकल्पित आधार संबंधी अपेक्षा को पूरा करना जरूरी नहीं होता है। तथापि, दूसरी ओर प्राधिकारी यह कहते हैं कि चूंकि टी सी एल का उत्पादन जांच अवधि के दौरान कुल उत्पादन का केवल 19.6 प्रतिशत बनता है, इसलिए वह नियम 2(ख) के भीतर घरेलू उद्योग के लिए क्षति निर्धारित नहीं कर सकता। पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य समान उत्पाद के ऐसे घरेलू उत्पादकों को संतत संरक्षण प्रदान करना है जिन्हें वास्तविक क्षति हुई है अथवा क्षति होने की संभावना है।

II. प्राधिकारी एम पी एल तथा टी सी एल द्वारा अपनाई गई उत्पादन की पद्धतियों के बीच भेद करने में विफल रहे हैं। संबद्ध वस्तु अर्थात् एम. ए. एन. की उत्पादन एम पी एल द्वारा थैलिक एनहाइड्राइड का उत्पादन करते समय एक सह उत्पाद के रूप में किया जाता है। अतः एम पी एल के लिए की उत्पादन लागत अत्यंत कम होती है और अत्यंत कम कीमतों पर अपने ग्राहकों को बिक्री कर सकती है जबकि टी सी एल द्वारा एक स्वतंत्र उत्पाद के रूप में एम ए एन का उत्पादन किया जाता है। यह एम ए एन के उत्पादन हेतु एक अनन्य संयंत्र चलाती है। इस संयंत्र में किए गए निवेश की कुल

राशि है आज की तारीख को लगभग *** करोड़ रुपए है । अतः एम पी एल की तुलना में टी सी एल के निष्पादन का आकलन करना अनुचित है ।

III. इसके अलावा, यदि यह मान लिया जाए कि टी सी एल नियम 2(ख) के भीतर घरेलू उद्योग नहीं हैं तो इससे पाटनरोधी शुल्क जारी रखना बंद नहीं होता है । पाटनरोधी सुरक्षा उन मामलों में भी प्रदान की जाती है जिनमें पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की स्थापना में वास्तविक व्यवधान पहुंचता है । घरेलू उद्योग भारतीय बाजार में अपना उत्पादन बढ़ाने तथा भारत में स्वदेशी रूप से विनिर्मित उत्पाद के लिए जगह तलाशने की भरपूर कोशिश कर रहा है । तथापि, संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग अपने उत्पाद का वाणिज्यीकरण करने से वंचित हुआ था । अतः पाटित आयातों से न केवल घरेलू उद्योग को क्षति हुई है अपितु, घरेलू उद्योग की स्थापना में वास्तविक व्यवधान भी उत्पन्न हुआ है । प्राधिकारी ने मामले के इस पहलू की कोई जांच नहीं की है ।

IV. इसके अलावा, प्राधिकारी का दायित्व किसी समीक्षा जांच में वर्तमान क्षति का निर्धारण करने का नहीं होता है । अतः यह तथ्य कि टी सी एल का उत्पादन कुल उत्पादन का मात्र 19.6 प्रतिशत बनता है, क्षति निर्धारण का कोई हेतु नहीं है । माननीय उच्चतम न्यायालय ने ऋषिरूप पॉलिमर्स प्रा. लि. बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी, 2006 (196) ई एल टी 385 (एस सी) ने समीक्षा के प्रयोजन और क्षेत्र पर निम्नानुसार विचार किया है:

अन्यथा भी हमारी राय यह है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा समीक्षा जांच का दायरा इस बात की संतुष्टि तक सीमित है कि क्या उसे प्राप्त सूचना के अनुसार ऐसे शुल्क को सतत रूप से जारी रखने का औचित्य है । इसके स्वरूप से ही समीक्षा जांच यह देखने तक सीमित हो जाएगी कि क्या पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के समय मौजूद स्थितियों में इतना अधिक परिवर्तन हुआ है कि शुल्क को निरंतर जारी रखने का अब औचित्य नहीं रह गया है । जांच सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत, पाटन मार्जिन, क्षति रहित कीमत के निर्धारण और घरेलू उद्योग को हुई क्षति जैसे विभिन्न मापदंडों में परिवर्तन तक सीमित होती है । उक्त जांच को विभिन्न मापदंडों में परिवर्तन के संबंध में प्राप्त सूचना तक सीमित रखना होगा । समीक्षा जांच का समग्र प्रयोजन यह देखना नहीं है कि क्या पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की जरूरत है अपितु, यह देखना है कि क्या शुल्क को इस प्रकार जारी न रखे जाने से पाटन में वृद्धि होगी और घरेलू उद्योग को क्षति होगी ।

V. कोई समीक्षा अपने स्वरूप से ही पाटनरोधी शुल्क को निरंतर लागू रखने की जरूरत के निर्धारण हेतु "परिवर्तित परिस्थितियों" की जांच तक सीमित होती है । वर्तमान मामले में यह साफ हो जाता है कि टी सी एल वस्तु के अत्यधिक पाटन के कारण संबद्ध वस्तु का विनिर्माण करने में समर्थ नहीं है । यह तथ्य कि टी सी एल का

उत्पादन बढ़ा है, से उच्चतर दर पर शुल्क को निरंतर लागू रखने का औचित्य मजबूत होता है । यदि प्राधिकारी प्रतिकूल दृष्टिकोण अपनाते हैं तो इस मामले में ही नहीं अपितु आगे के मामलों में भी इसके घातक परिणाम होंगे । ऐसे किसी अभिमत का लाभ उठाते हुए कोई निर्यातक मूल जांच के बाद अपना पाटन आगे और तेज करेगा और घरेलू उत्पादकों को योजनाबद्ध ढंग से नेस्ताबूत कर देगा । उत्पादन को पूर्ण या आंशिक रूप से बंद किए जाने से निर्यातक यह तर्क देते हुए मध्यावधिक समीक्षा शुरू करने का अनुरोध करेगा कि शुल्क को जारी रखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि कोई घरेलू उद्योग है ही नहीं । यह पाटनरोधी कानून जैसे व्यापार निवारण उपायों के उद्देश्य के प्रतिकूल होगा । वस्तुतः कनाडा इंटरनेशनल ट्रेड ट्रिब्यूनल के सामने कार्बन स्टील वेल्डेड पाइप के आयातों से संबंधित विशेष आयात उपायों की धारा 76(2) के अंतर्गत एक पाटनरोधी समीक्षा जांच में ऐसा ही प्रश्न आया था (जांच परिणाम अनुबंध-1 में संलग्न हैं)। इस मामले में पाटनरोधी शुल्क की सुरक्षा के 17 वर्ष बाद भी घरेलू उद्योग ने संयंत्र बंद कर दिए और उसकी वित्तीय स्थिति काफी खराब रही थी । ट्रिब्यूनल ने निम्नानुसार निर्णय दिया :

“जहां तक क्षति के मुद्दे का संबंध है, ट्रिब्यूनल ने यह नोट किया कि समूचे 1990 के दशक के दौरान घरेलू उद्योग ने संयंत्र बंद रखने और उत्पादन को युक्तिसंगत बनाया तथा साथ नई, आधुनिकतम उत्पादन सुविधाओं में भारी निवेश किया । इसके होते हुए भी बिक्रियां स्थिर रही थीं, घरेलू उद्योग क्षमता के कम स्तर पर प्रचालन कर रहा था और समग्र वित्तीय निष्पादन खराब रहा था । वस्तुतः ट्रिब्यूनल ने यह नोट किया कि कनाडा में मानक पाइप उद्योग के पिछले दो दशकों के दौरान कुछ ही वर्ष बेहतर रहे थे जबकि कोरियाई पाइप पर 17 वर्ष तक पाटनरोधी शुल्क का संरक्षण लागू रहा था । इस तथ्य से ट्रिब्यूनल ने यह माना कि उद्योग के भीतर ऐसी समस्याएं हैं जो उनके नियंत्रण से बाहर की हैं, जिन्हें पाटनरोधी उपायों द्वारा सुधारा जा सकता है । ट्रिब्यूनल की राय में आदेश को जारी रखने से घरेलू उद्योग के वर्तमान निष्पादन में स्वतः सुधार नहीं होगा । लेकिन आदेश निरस्त किए जाने से उद्योग निश्चित तौर पर खराब स्थिति में पहुंच जाएगा । ”

VI. उपर्युक्त जांच में ट्रिब्यूनल ने यह भी पाया कि पाटन से इतर भी कारण थे जिसकी वजह से घरेलू उद्योग को क्षति हुई थी । लेकिन ट्रिब्यूनल का यह मत था कि पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने से घरेलू उद्योग की स्थिति आगे और खराब हो जाएगी । अतः प्राधिकारी की ओर से यह निष्कर्ष निकालना अतार्किक होगा कि टी सी एल की उत्पादन मात्रा और कुल भारतीय उत्पादन में उसके हिस्से में आई गिरावट की वजह से पाटनरोधी शुल्क को निरंतर जारी रखे जाने की कोई जरूरत नहीं है । प्राधिकारी के लिए यह देखना अपेक्षित होता है कि क्या पाटनरोधी शुल्क के अभाव में पाटन में वृद्धि होगी और टी सी एल को आगे और क्षति होगी । यह स्पष्ट है कि यदि पाटनरोधी शुल्क समाप्त किया जाता है तो पाटन में आगे और तेजी आएगी और टी सी

एल बाजार से चरणबद्ध रूप से विलुप्त हो जाएगा । इस तथ्य कि टी सी एल के उत्पादन में गिरावट आ गई है, से टी सी एल को हुई क्षति की गंभीर और खतरनाक स्थिति सिद्ध होती है ।

- VII. अर्जेन्टीना से ऑयल कंट्री टुबुलर गुड्स पर पाटनरोधी उपायों की निर्णायक समीक्षा में संयुक्त राज्य में अपीलीय निकाय की रिपोर्ट - डब्ल्यू टी/डीएस 268/एबी/आर के मद्देनजर उपर्युक्त तर्क को आगे और बल मिलता है ।

279. क्षति निर्धारण की संभावना पर अनुच्छेद 3 लागू करने के पर्याप्त पाठ संबंधी आधार के अभाव में आश्चर्यजनक ढंग से "एक ओर मूल जांच और दूसरी ओर निर्णायक समीक्षा के अलग स्वरूप और प्रयोजन" का उल्लेख नहीं किया गया है जिस पर अमरीका में अपीलीय निकाय ने कोरोजन रेसिस्टेंट इस्पात की निर्णायक समीक्षा में बल दिया था । मूल जांच में पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के लिए जांच प्राधिकारी हेतु अनुच्छेद 2 के अनुसार पाटन की मौजूदगी का निर्धारण करना और बाद में अनुच्छेद 3 के अनुसार यह निर्धारण करना अपेक्षित है कि क्या घरेलू उद्योग को मूल जांच के समय क्षति हो रही है या उसका खतरा उत्पन्न हो गया है । इसके विपरीत अनुच्छे 11.3 में किसी जांच प्राधिकारी के लिए पाटनरोधी शुल्क लागू रखने, पाटन एवं क्षति के पूर्वापेक्षित निर्धारण का पालन करते हुए पहले से विद्यमान पाटनरोधी शुल्क संबंधी आदेश की समीक्षा करना अपेक्षित है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या उक्त आदेश को जारी रखा जाना चाहिए या रद्द कर दिया जाना चाहिए ।

280. पाठ संबंधी प्रति संदर्भ के अभाव में और इन दोनों निर्धारणों के अलग-अलग स्वरूप और प्रयोजन को देखते हुए हमारा यह मत है कि अनुच्छेद 3 के अनुसार पहले से पुष्टिकृत क्षति के निर्धारण की "समीक्षा" हेतु अनुच्छेद 11.3 में यह अपेक्षित नहीं है कि अनुच्छेद 3 के अनुसार क्षति का पुनः निर्धारण किया जाए । अतः हमारा यह निष्कर्ष है कि जांच प्राधिकारी को क्षति निर्धारण की संभावना का आकलन करते समय अनुच्छेद 3 के प्रावधानों का पालन करने का अधिदेश नहीं है ।

- VIII. पाटनरोधी कानून के अंतर्गत कोई मध्यावधि समीक्षा सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9 क (5) में प्रदत्त अधिदेश के अनुसरण में की जाती है । उक्त प्रावधान डब्ल्यू टी ओ : पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 11.3 के समान है । भारतीय कानून में मध्यावधिक समीक्षा तथा निर्णायक समीक्षा में ऐसा कोई भेद नहीं है जैसा कि पाटनरोधी करार में प्रतीत होता है । इस प्रकार अनुच्छेद 11.3 के समान धारा 9 क (5) मध्यावधि समीक्षाओं में भी लागू होती है । अतः अपीलीय निकाय की रिपोर्ट को

ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी के लिए उस क्षति का पुनः निर्धारण करना अपेक्षित नहीं है जिसकी पुष्टि मूल जांच में की जा चुकी है। अतः नियम 2 (ख) के अनुसार, घरेलू उद्योग के बारे में निर्धारण करने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि क्षति का पुनः निर्धारण अपेक्षित नहीं है जैसा कि मूल जांच में किया जाता है।

- IX. पूर्वोक्त तथ्यों और विधिक तर्कों को ध्यान में रखते हुए अनुरोध है कि मूल जांच के समय प्रचलित परिस्थितियों में भारी परिवर्तन आया है। संबद्ध देशों ने संबद्ध वस्तु के पाटन में और अधिक तेजी लाई है। पाटन से घरेलू उद्योग की स्थापना पर भी वास्तविक व्यवधान पड़ा है। अतः अनुरोध है कि प्राधिकारी कृपया घरेलू उद्योग की सुरक्षा हेतु पाटनरोधी शुल्क के वर्तमान स्तर में उचित वृद्धि करें।

15. प्राधिकारी द्वारा जांच

प्रकटन विवरण के उत्तर में टी सी एल द्वारा दिए गए तर्कों की प्राधिकारी ने जांच की है और प्राधिकारी निम्नानुसार नोट करते हैं:-

(क) टी सी एल ने यह तर्क दिया है कि जहां तक प्राधिकारी की इस सहमति का संबंध है कि आधार संबंधी जरूरत नियम 5 के अंतर्गत पूर्वापेक्षा नहीं है और साथ ही साथ प्राधिकारी घरेलू उद्योग को क्षति का निर्धारण इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि टी सी एल का उत्पादन कुल उत्पादन का मात्र 19.6 प्रतिशत है, प्राधिकारी का वक्तव्य विरोधाभासी है। प्राधिकारी यह मानते हैं कि उक्त वक्तव्य में कोई विरोधाभास नहीं है। नियम 5 के अंतर्गत आधार संबंधी अपेक्षाएं तथा नियम 2 (ख) के अंतर्गत घरेलू उद्योग का क्षेत्र दो अलग-अलग अपेक्षाएं हैं। चूंकि नियम 23 में नियम 5 का उल्लेख नहीं है इसलिए प्राधिकारी ने यह निष्कर्ष निकाला कि मध्यावधि समीक्षा की शुरुआत के प्रयोजनार्थ नियमों के अंतर्गत आधार की अपेक्षा नहीं है। तथापि, यह केवल जांच की शुरुआत का अनुरोध करते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत आवेदन के संबंध में ही है। चूंकि नियम 23 में नियम 5 का उल्लेख नहीं है, इसलिए प्राधिकारी जांच शुरू करने के लिए न्यायोचित है भले ही भारतीय उत्पादन में याचिकाकर्ता के उत्पादन का हिस्सा कुछ भी हो। तथापि, यदि याचिकाकर्ता के उत्पादन का हिस्सा नियमों के अर्थ के भीतर भारतीय उत्पादन में एक प्रमुख हिस्सा नहीं बनता है तो ऐसा याचिकाकर्ता नियम 2 (ख) की परिभाषा के भीतर घरेलू उद्योग नहीं बन सकता। प्राधिकारी ने सतत रूप से यह दृष्टिकोण अपनाया है कि यदि याचिकाकर्ता का हिस्सा 25 प्रतिशत से कम है तो यह नियम 2 (ख) में ही प्रदत्त अपवादों को छोड़कर नियम 2 (ख) के अर्थ के भीतर एक बड़ा अनुपात नहीं बन सकता। वर्तमान मामले में जाहिर तौर पर विचाराधीन उत्पाद के दो उत्पादक हैं। दूसरी कंपनी का उत्पादन 80 प्रतिशत से अधिक है और याचिकाकर्ता का उत्पादन 25 प्रतिशत से कम है। अतः प्राधिकारी नियम 2 (ख) के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग के रूप में याचिकाकर्ता पर विचार नहीं कर सकते। इसके अलावा, जैसा कि अन्यत्र नोट किया गया है, प्राधिकारी के लिए घरेलू उद्योग को परिभाषित करने के बाद क्षति का निर्धारण करने और तत्पश्चात ऐसे घरेलू उद्योग को हुई क्षति का निर्धारण करना अपेक्षित होता है। वर्तमान मामले में चूंकि प्राधिकारी टी सी एल पर घरेलू उद्योग के रूप में विचार करने में असमर्थ हैं, इसलिए प्राधिकारी घरेलू उद्योग को हुई क्षति का निर्धारण नहीं कर सकते।

(ख) जहां तक टी सी एल और एम पी एल द्वारा अपनाई गई उत्पादन पद्धतियों में अंतर का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि नियम 2 (ख) में संबद्ध उत्पाद के उत्पादन की अलग-अलग पद्धतियों के बीच भेद नहीं किया गया है। नियम 2 (ख) में "उत्पादन" का उल्लेख है और इस प्रकार उत्पादन की पद्धतियां पूर्णतः अप्रासंगिक हैं। यदि उत्पादन सह उत्पाद की पद्धति के जरिए होता है तो भी यह पाटनरोधी नियमों के प्रयोजनार्थ उत्पादन बनता है। इस प्रकार उत्पादन की पद्धतियां घरेलू उद्योग के क्षेत्र को परिभाषित करने में पूर्णतः निराधार हैं।

(ग) जहां तक टी सी एल के इस तर्क का संबंध है, यद्यपि वह घरेलू उद्योग नहीं है, तथापि, इससे पाटनरोधी शुल्क को जारी रखना समाप्त नहीं हो जाता है और नियमों में "घरेलू उद्योग की स्थापना के लिए अत्यधिक व्यवधान" को स्वीकार किया गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान आवेदन पाटनरोधी शुल्क में उर्ध्वगामी संशोधन की मांग करते हुए टी सी एल द्वारा और पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति की मांग करते हुए विभिन्न प्रयोक्ता एसोसिएशनों अर्थात् मै. इंडियन प्लास्टीसाइजर्स मैन्यु. एसो. तथा मै. पॉलिएस्टर रेजिन मैन्यु. एसो. द्वारा दायर किया गया है। यद्यपि, यह माना जाता है कि नियमों में पाटनरोधी शुल्क जारी रखने की अनुमति है और नियमों में घरेलू उद्योग की स्थापना में अत्यधिक व्यवधान की संस्तुति की गई है। तथापि, क्षति के रूप में प्राधिकारी द्वारा "घरेलू उद्योग" पर विचार करने की परिकल्पना दोनों प्रावधानों में की गई है। घरेलू उद्योग की स्थापना में वास्तविक व्यवधान की परिकल्पना भी "घरेलू उद्योग" के निर्धारण के लिए की गई है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग को सतत क्षति की परिकल्पना भी "घरेलू उद्योग के क्षेत्र" के संबंध में की गई है। दूसरे शब्दों में पाटनरोधी शुल्क की अवधि में तब तक विस्तार/राशि में वृद्धि अथवा संशोधन नहीं किया जा सकता जब तक कि प्राधिकारी नियम 2 (ख) के भीतर ऐसे "घरेलू उद्योग" की पुष्टि न करें जिसके आंकड़ों पर क्षति के निर्धारण हेतु भरोसा किया जा सकता हो। वर्तमान मामले में प्राधिकारी ऐसी कंपनियों का निर्धारण करने में असमर्थ हैं जिनके आंकड़ों पर क्षति के निर्धारण हेतु भरोसा किया जा सकता हो। यद्यपि, टी सी एल का उत्पादन 25 प्रतिशत की न्यूनतम सीमा से कम है, तथापि अन्य घरेलू उत्पादक ने संगत क्षति संबंधी सूचना के साथ प्राधिकारी से सहयोग नहीं किया है। चूंकि प्राधिकारी वर्तमान मामले में घरेलू उद्योग के घटकों को परिभाषित करने में समर्थ हैं, इसलिए प्राधिकारी इस बात पर विचार नहीं कर सकते कि क्या घरेलू उद्योग को क्षति हुई है या क्षति होने की संभावना है।

(घ) जहां तक इस तर्क का संबंध है कि पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग उत्पादन का वाणिज्यीकरण करने से वंचित हुआ है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि टी सी एल नियम 2 (ख) के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग की मौजूदगी सिद्ध करने में विफल रही है। इसके अलावा, ऐसी किसी कंपनी के लिए उत्पादन के वाणिज्यीकरण का प्रश्न नहीं उठता जो पहले से वाणिज्यिक उत्पादन कर रही है और जिसने बाद में उत्पादन घटा दिया है।

(ड) जहां तक टी सी एल द्वारा ऋषिरूप पालिमर प्रा.लि. बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उक्त निर्णय "घरेलू उद्योग के गठन" पर आधारित है। परंतु, वर्तमान मामले में प्राधिकारी घरेलू उद्योग का गठन करने में असमर्थ हैं। इसलिए माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय को लागू करने का प्रश्न नहीं उठेगा।

(च) जहां तक टी सी एल के स्तर का संबंध है, कि उत्पाद का पाटन तेज किए जाने के परिणामस्वरूप टी सी एल ने उत्पादन घटाया है और इससे उच्चतर दर पर पाटनरोधी शुल्क को सतत रूप से लगाया जाना न्यायोचित बनता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति के निर्धारण हेतु टी सी एल के आंकड़े तभी व्यवहार्य होंगे जब प्राधिकारी इस निर्णय पर पहुंचेंगे कि टी सी एल नियम 2 (ख) के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग है। प्राधिकारी के इस निष्कर्ष को देखते हुए कि टी सी एल घरेलू उद्योग नहीं है, टी सी एल का निष्पादन नितांत अप्रासंगिक है।

(छ) टी सी एल ने प्राधिकारी का ध्यान कार्बन स्टील वेल्डेड पाइप के मामले में कनाडियन प्राधिकारियों के निर्णय की ओर आकर्षित किया है तथा प्राधिकारी यह मानते हैं कि टी सी एल ने यह निर्धारित नहीं किया है कि कनाडियन प्राधिकारियों का उक्त निर्णय घरेलू उद्योग और उसके घटकों को परिभाषित किए बिना दिया गया है। वर्तमान मामले में पूर्व में किए गए उल्लेखानुसार प्राधिकारी ऐसे घरेलू उद्योग के क्षेत्र का निर्धारण नहीं कर सकते जिसे हुई क्षति की जांच की जा सके।

(ज) टी सी एल ने यह तर्क दिया है कि प्राधिकारी के लिए इस बात पर विचार करना अपेक्षित है कि क्या पाटनरोधी शुल्क के अभाव में पाटन में वृद्धि होगी और क्या टी सी एल को आगे और क्षति होगी। तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि नियमों में किसी कंपनी को हुई क्षति की जांच का प्रावधान नहीं हो। नियमों में "घरेलू उद्योग को हुई क्षति" के निर्धारण का प्रावधान है। इस प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग के लिए नियम 2 (ख) की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए परिभाषित/गठित करना अपेक्षित है।

(झ) टी सी एल ने संयुक्त राज्य-अर्जेंटीना से ऑयल कंट्री टुबुलर गुड्स के मामले में पाटनरोधी उपायों की निर्णायक समीक्षा में डब्ल्यू टी ओ के निर्णय का हवाला दिया है। प्राधिकारी यह मानते हैं कि उक्त निर्णय "घरेलू उद्योग" के बारे में सकारात्मक निर्धारण पर पुनः आधारित है। तथापि, वर्तमान मामले में प्राधिकारी ऐसे घरेलू उद्योग का निर्धारण करने में असमर्थ हैं जिसे हुई क्षति की जांच की जा सके।

(ट) टी सी एल ने यह तर्क दिया है कि धारा 9 (5) अनुच्छेद 11.3 के समान है, निर्दिष्ट प्राधिकारी और भारतीय कानून में मध्यावधि समीक्षा और निर्णायक समीक्षा के बीच कोई भेद नहीं किया है। प्राधिकारी मानते हैं कि यह मुद्दा पूर्णतः अप्रासंगिक है। प्राधिकारी के लिए घरेलू उद्योग के क्षेत्र को परिभाषित/निर्धारित करना अपेक्षित है चाहे नई जांच हो या कोई मध्यावधिक समीक्षा या कोई निर्णायक समीक्षा। यदि घरेलू उद्योग के गठन की ही पुष्टि नहीं हो सकती तो प्राधिकारी घरेलू उद्योग को हुई क्षति की मौजूदगी अथवा अन्यथा की पुष्टि नहीं कर सकते।

16. निष्कर्ष

विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों और खासकर टी सी एल द्वारा किए गए अनुरोधों, प्रकटन विवरण पर उनकी टिप्पणियों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद और विधिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी यह मानते हैं कि वर्तमान मामले में नियमों में “घरेलू उद्योग को हुई क्षति” की जांच करना अपेक्षित है जिसके लिए प्राधिकारी की ओर से “घरेलू उद्योग” को परिभाषित/निर्धारित करना अपेक्षित होता है। वर्तमान मामले में टी सी एल का उत्पादन भारतीय उत्पादन का एक बड़ा भाग नहीं बनता है। इसलिए प्राधिकारी टी सी एल पर घरेलू उद्योग के रूप में विचार करने में असमर्थ हैं। एकमात्र अन्य घरेलू विनिर्माता का उत्पादन भारतीय उत्पादन के 80 प्रतिशत से अधिक बनता है और उसने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है और घरेलू उद्योग को हुई क्षति के निर्धारण के संगत कोई सूचना प्रदान नहीं की है। अतः प्राधिकारी यह निर्धारित करने में असमर्थ हैं कि क्या उत्पाद के आरोपित बढ़ते हुए पाटन के कारण नियमों में निर्धारित किसी रूप में घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है अथवा क्षति होने की संभावना है। इसके अलावा, पूर्वोक्त को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी यह निर्धारित करने में असमर्थ हैं कि क्या विचाराधीन उत्पाद के ऐसे आयातों से “घरेलू उद्योग” से क्षति संबंधी पर्याप्त सूचना के अभाव में घरेलू उद्योग को क्षति हुई है। इस बात को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से पाटन की मौजूदगी/मात्रा के बारे में निर्धारण नहीं किया है और न ही प्राधिकारी ने इस बात की जांच की है कि क्या संभावित क्षति स्पष्ट पाटित आयातों के कारण हुई है।

17. जांच परिणाम

(क) पूर्वोक्त पर तथा प्रकटन विवरण पर प्राप्त टिप्पणियों पर विचार करने के बाद प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि सबद्ध देशों से हुए आयातों के कारण कोई घरेलू उद्योग प्रभावित नहीं हुआ है।

(ख) उपर्युक्त को देखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी अधिनियम की धारा 9(क) (5) के अनुसार 18 सितंबर, 2008 की अधिसूचना सं. 105/2008 द्वारा अधिसूचित संबद्ध देशों के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के बारे में लागू पाटनरोधी शुल्क को समाप्त करने की सिफारिश करना उचित समझते हैं।

(ग) इस सिफारिश के परिणामस्वरूप केन्द्र सरकार के आदेशों के खिलाफ कोई अपील अधिनियम के संगत उपबंधों के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण में दायर की जा सकेगी।

पी. के. चौधरी, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st August, 2010

Mid-term Review Findings

Subject : Mid-term review findings in respect of Anti-dumping investigation concerning imports of Maleic Anhydride (MAN) originating in or exported from the China PR, Chinese Taipei and Indonesia.

No. 15/11/2009-DGAD.—Background

1. The procedure described below has been followed with regard to this investigation:-

(i) The final findings in respect of the original investigation was issued vide Notification Number 14/3/2007-DGAD dated 22th August, 2008 and a corrigendum to the final findings on 5th Sep., 2008 and whereas definitive anti-dumping duties were imposed on the subject goods originating in or exported from the subject countries vide Customs Notification No. 105/2008 Customs dated 18th September, 2008.

(ii) M/s Thirumalai Chemicals Ltd (TCL), Ranipet, the domestic industry, has submitted an application for mid-term review of the anti-dumping duties imposed vide Customs Notification No. 105/2008 dated 18th September, 2008, in respect of the imports of the subject goods Maleic Anhydride(MAN) originating in or exported from the China PR, Chinese Taipei and Indonesia. It was stated by the Domestic Industry that due to lack of protection from dumped imports, TCL (M/s. Thirumalai Chemicals Ltd.) was forced to close their total operations before the duties could be imposed. It was stated that the company is producing Maleic Anhydride in their plant. The company was forced to shut its operations due to very high cost of production and due to huge price undercutting due to cheaper imports. The company has provided the import data for earlier years (2005-06, 2006-07 and 2007-08) based on DGCI&S and for the period 2008-09 based on IBIS. The support letter from another producer namely M/s Mysore Petrochemicals Ltd has also been provided and it was stated that the company will provide

information upon the initiation. The company has requested for initiation of midterm review in view of these changed circumstances.

- (iii) M/s. Polyester Resin Manufacturer's Association have requested to initiate a mid-term review because of changed circumstances as M/s TCL have stopped production of Maleic Anhydride and there is no domestic industry. They have submitted copies of import data based on IBIS for the period Jan-Oct. 2009 to support their claim. It is submitted that based on the data available from IBIS, the DI(TCL) have directly or through their agents imported large quantity of the subject goods from their own plant in Malaysia and through M/s. Ransom PTE Limited, Singapore which is their own front. It is contended that there is no operational plant in Singapore of this product which clearly indicates that these goods are of Malaysia origin and are merely routed via Singapore. Because of such imports from Malaysia, TCL have shut down their production facilities in India. It is prayed that as there is no domestic production of the subject merchandise in India, the very rational of imposition of anti-dumping duties-injury caused to domestic industry because of dumped imports-stands destroyed.
- (iv) M/s Indian Plasticizers Manufacturers Association, have also requested for a review of the anti-dumping duty in the aforesaid case. It is submitted that the production shown by M/s. TCL for the year 2007-08 and 2008-09 is on account of their own imports which can be verified from import data. In fact, TCL have abandoned the production of Maleic Anhydride. It has been stated in their Annual Report of 2008-09 that they have discontinued Maleic Anhydride production and their own captive requirement of this product is being catered through imports since imports are more economical and viable than producing. It is stated that TCL is importing this product through their associates namely BMG Chemicals Pvt. Ltd. They have submitted the import data of Maleic Anhydride from August-November, 2009 and the relevant portion of their Annual Report of 2008-09. In view of the above circumstances, a review of anti dumping measures in force is necessary.
- (v) Having regard to the information provided by the applicants indicating changed circumstances necessitating a review of the measure in force, the Designated authority considered that a mid-term review of the final findings notified vide No. 14/03/2007-DGAD dated 22.08.2008 and the Definitive anti dumping duty imposed by Customs Notification No.105/2008 dated 18th September, 2008 is appropriate in view of the changed circumstances, in terms of the provision of Section 9(A) of

Customs Tariff (Amendment) Act 1995 read with Rule 23 supra. Accordingly, the review was initiated vide Notification No.15/11/2009-DGAD dated 11th February, 2010. The review covers all aspects of Notification No. 14/03/2007-DGAD dated 22.08.2008.

- (vi) The Authority sent copies of initiation notification dated 11.02.2010 to the Embassies of the subject countries in India, known exporters from the subject countries, importers and the domestic industry as per the addresses available, and requested them to make their views known in writing within 40 days of the initiation notification.
- (vii) The Authority provided copies of the non-confidential version of the application to the known exporters and to the Embassies of subject countries in accordance with Rule 6(3) supra.
- (viii) The Authority sent questionnaires, to elicit relevant information to the known exporters in subject countries in accordance with Rule 6(4).
- (ix) In response to the above said notification, the aforesaid associations and the domestic industry responded.
- (x) In response to the above notification, none of the exporters have responded to the questionnaire, except M/s D.D.International, on behalf of Shanxi Regent Works, China PR.
- (xi) Importers namely M/s Jaydip Agencies, Mechemco Resins Pvt Ltd, Rachna Plasticizers, KLJ Silvassa Plast, Visen Industries have responded and provided the information in respect of imports made by them during 2006-07, 2007-08 and the POI.
- (xii) The Period of Investigation (POI) for the purpose of the present mid-term review is from April 2008 to September, 2009 (18 months). However, injury analysis shall cover the years 2005-06, 2006-07, 2007-08 & POI.
- (xiii) Request was made to the DGCI&S to arrange details of imports of subject goods for the past three years and the period of investigation. Data has since been received from DGCI&S, and has appropriately been replied upon in this finding.
- (xiv) The Authority carried out the verification at the premises of the domestic industry.

- (xv) The Authority held a public hearing on 9.2.2010 to hear the interested parties orally. The parties attending the public hearing were requested to file written submissions of views so expressed orally.
- (xvi) *** in this finding represents information furnished by the interested parties on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
- (xvii) In accordance with Rule 16 of the Rules supra, the Authority disclosed the essential facts considered for these findings, on 21st July 2010 by giving adequate notice, to known interested parties and comments received on the same have been considered at appropriate places in this finding.

2. Submissions made subsequent to the Public hearing

By TCL - The submissions made by TCL have been summarized as follows:

- TCL has reduced the production, but never stopped production. The company continues to be in production of the product.
- There are two producers of the product concerned in India i.e. TCL and Mysore Petrochemicals (MPL) whose production details are as follows:

Year	Production			TC % in Total Production
	TCL	MPCL	Total	
2005-06	***	***	***	81.1%
2006-07	***	***	***	79.8%
2007-08	***	***	***	43.3%
2008-09	***	***	***	22.3%
POI	***	***	***	19.6%
POI-Annualized	***	***	***	19.6%

- TCL has imported the subject goods. However, reasons for imports are substantially different from what has been argued by the other interested parties. There was a significant difference in the prices of domestic

industry goods and imports. In spite of the increase in the global prices of the raw material (benzene), the prices of the imports never showed any appreciable changes, due to which the company was unable to increase its prices in line with cost increases and were left with no option but to import and resell it in order to cater to the needs of the customers. Imports from Malaysia increased only during 2008-09. Prior to this period, imports by TCL constituted only 7.22% of the total imports. The fact that TCL was not importing the product prior to 2008-09, which clearly proves that TCL never intended to import from its Malaysian plant

- iv. TCL has invested significant amount in the Indian Plant which is much higher than what it has invested in Malaysian Plant. No prudent business entity would allow its capital worth crores of Rupees to remain idle and opt for imports. Malaysian plant is undergoing liquidation process. So it would be illogical to shut down its profitable venture to protect a plant under liquidation proceedings.
- v. TCL had made few attempts to restart its production but could not do so due to dumped imports and therefore had to shut down its plant. The AD Duty imposed is grossly inadequate and did not consider the damage that had occurred in Oct 2006-Sep2008. During this period the imports had increased significantly from 11416MT in 2006-07 to 19983 MT in 2007-08 at further dumped prices.
- vi. The non-cooperation from the exporters only suggests that the actual level of dumping is much higher than projected by the domestic industry.
- vii. Imports of the subject goods have caused injury to the domestic industry, as is established by the followings.
 - a. Imports have increased in absolute terms. Within a period of 4 years the imports have increased by 97%.
 - b. Imports have also increased relatively. In 2005-06, dumped imports constituted 62% of total production which has increased manifold to 553% during POI 2008 -09.
 - c. In 2005-06, dumped imports constituted 40% of total consumption. The same has increased to 49% of consumption during 2008-09.
 - d. Despite the increase in cost of production, the landed price of the imports remained the same. There is significant price depression and price suppression due to dumped imports.

- e. The sales quantity of the domestic industry has declined to 769 Mt in POI
- f. The domestic industry was having 96% market share during 2001-02 when there were no dumped imports. The same declined to 5% in 2007-08 and further fell down to 1.7% during POI.
- g. Capacity utilization has decreased from 59% in 2005-06 to a meager 3% during POI.
- h. Production has fallen steeply from 10,442 MT in 2005-06 to 847 MT during POI
- i. TCL has a state of the art plant and machinery and they did not record any fall in productivity.
- j. Domestic Industry made profits during 2005-06 but thereafter suffered losses in the subsequent years.
- k. Return on Investments declined significantly because of presence of dumped imports, which declined to a negative 20.49% during POI.
- l. Domestic Industry earned cash profits during 2005-06 but suffered cash losses in subsequent years due to dumped imports.
- m. There is a fall in inventory since 2006-07, as there has been significant low volumes of production and sales
- n. Employment has been adversely affected due to fall in production. However, none of employees were retrenched and were redeployed for the manufacture of Pthalic Anyhydride (PAN.)
- o. Wages per person declined during POI as the allocation of salary of Maleic Anhydride plant staff to other plants
- p. There is no contradiction in demand as it kept on increasing during the injury period and even in POI. On the other hand domestic sales declined.
- q. Inspite of increase in installed capacity the production capacity of the Domestic Industry remained idle. Consumption of the product increased upto 70% but still the Domestic Industry was unable to increase their production or sales.
- r. Since the return on capital employed is negative (i.e. – 20.5%), ability to raise capital or investments has been severely affected.

- s. The petitioner was in a position to get remunerative prices before dumping started. But they were compelled to reduce their prices due to dumped prices.
 - t. Import price are so low that they appear to be lower than the variable cost of the domestic production indicating aggressive dumping.
 - u. In addition to the material injury and threat of injury, the dumped imports have also materially retarded the establishment of the domestic industry in India. The intense dumping of goods has resulted into erratic production of subject goods by TCL. In fact, the dumping is so intense that even after several attempts TCL had to shut down its plants after a brief run.
 - v. The domestic industry has increased its capacity in 2005 but the presence of dumped imports prevented the utilization of capacity so expanded. Due to dumped imports the domestic industry had to curtail its production in 2007-08. In fact, the capacity utilization was so low in 2007-08 that the domestic industry was unable to utilize capacity existing prior to the commencement of the dumped imports into India. Dumped imports had barred the domestic industry from commercializing its product.
- viii. Injury to the domestic industry has been caused by dumped imports. The imports from Malaysia and Korea have increased as the domestic industry remained shut down due to large scale imports of dumped goods from the subject countries. However, the average price per MT from China was much lower than the average price per MT in Malaysia during all the months except April 2009, July 2009 and August 2009. The injury suffered by the domestic industry due to dumped imports is the cause of the increase in imports from non-subject countries.
- a. Contraction in Demand: there has been consistence increase in demand of the product. Therefore contraction in demand is not the factor affecting the Domestic Industry.

- b. Pattern of Consumption: there is no significant change in the pattern of consumption.
- c. Developments in Technology: there is no significant change in the technology.
- d. Conditions of Competition: there are no trade restrictive practices or anti-competitive practices prevailing in India.
- e. Export performance of the domestic industry: the Domestic Industry's financial or economic condition is not affected by its export performance. The data pertaining to export has been excluded from the preceding paragraph for the purpose of injury determination.

3. Submissions made by M/s Mysore Petrochemicals Ltd (MPL) – MPL have supported the request for enhancement of anti dumping duty filed by TCL. The company has however not provided any information relevant to the present investigations. MPL has not disputed the claim of the opposing interested parties that the product under consideration is a byproduct for MPL and MPL could not have suffered material injury from imports.

4. Submission made by associations

4.1 M/s. Polyester Resin Manufacturer's Association –

- a) No evidence on Dumping on account of non-submission of requisite data within the prescribed time limit – TCL failed to submit any evidence regarding change in normal value, export price, landed value and non-injurious price of the domestic industry. Therefore, in the absence of evidence on dumping, the current review should be immediately terminated.
- b) In the absence of information on domestic industry, there is no question of any dumping or injury analysis. Continuing ADD will have cascading effect on prices of the end product and the market competitiveness of the TCL.
- c) TCL production had fallen by 94% since the original investigation. Also as per their 36th annual report, its plant was not operational for most of the parts in 2008-09. The downstream user industry has no other option but to import in view of the production curtailment.
- d) No question of "injury" to TCL on account of its negligible domestic production of the subject goods.

- e) Maleic Anhydride is a by-product of Pthalic Anhydride: it has been accepted by the Mysore Petrochemicals Ltd. (supporter in present investigations) at the earlier public hearing that Maleic Anhydride is a by-product of Pthalic Anhydride.
- f) Review should be terminated on account of break in the causal link. Despite imposition of ADD, the domestic production was stopped on the ground that the prices of benzene were unusually high. This claim cannot be given credence as there was a global increase in the benzene prices
- g) The injury is self inflicting. Market has expanded with the increase in demand but both domestic production and sales of the TCL have been abysmal in comparison to the increase in demand over the period of review.
- h) The drastic drop of production is solely due to imports of subject goods from Malaysia. Imports from Malaysia since the imposition of ADD had significantly increased. The market share of both the imports from Malaysia as well as domestic producer has increased during POI
- i) While there was no domestic production of the product. China and Indonesia are being subjected to anti dumping duty. Imports from Malaysia are controlled by TCL. TCL has thus created a monopoly. Injury to TCL is predominantly due to imports of subject goods from its own plant.
- j) Given that the interested exporter Yabang in the original investigation already has a case pending before the CESTAT in regards to the issue of Non Market Economy, it is not cooperating in the present investigation.

4.2 Submissions Made by Indian Plasticizers Manufacturers Association-

- i. None of the indigenous manufacturers have submitted the data for the above periods.
- ii. TCL have been importing the product since Aug 2009 and that too in significant quantity. Imports of Maleic Anhydride have been through their Associates namely BMG Chemicals Pvt. Ltd to the tune of 1260 tonnes. TCL and BMG Chemicals are importing MAN at other Ports in India too. Ranson Pvt. Ltd. Singapore is exporting MAN of TCL Malaysian Joint Venture to India. TCL are the major importer of PUC and do not qualify to be Domestic Industry.
- iii. Solicitors of TCL have mentioned that MAN by TCL is based on unviable technology benzene. This has forced them to discontinue MAN production

since 2007. To meet the captive requirement, TCL imported the product as it was more economical and viable than producing.

- iv. TCL has set up a Joint Venture in Malaysia for manufacture of MAN based on Butane since 2008. It is not understood why the same technology is not implemented in India. Had it been the case then the question of unviable Indian unit would not have arisen.
- v. TCL has malafide intentions of protecting and giving unjust benefit to Malaysian Joint Venture at the cost of Indian consumer industry. Their transaction price is null & void as it is a sister concern.
- vi. The manufacturers do not come under anti dumping but under safeguards. The TCL should submit the detailed restructure plan to facilitate positive adjustment of the industry and the time period needed to remove the injury/market disruption of the domestic industry.
- vii. The purpose of initial duty as well as review is to provide protection to the joint venture in Malaysia. The purchases shown are the imports from the Malaysia plant. Moreover MPL cannot be classified as a manufacturer of MAN as they obtain MAN as a by-product during the production of Phthalic Anhydride.
- viii. TCL is a highly profitable company paying high dividends to its shareholders. TCL net profits has been Rs. 2585 Lakhs as per audited report ending 31.03.2010 against their losses of Rs. 4600 Lakhs during 2008 – 09. There is no injury to the local industry at present.
- ix. As per Audited Financial Report of TCL for the quarter ended 31.03.2010, the Hon'ble High Court, Bombay has approved the write down of the amount of Investment of about Rs. 183 Lakhs made in the ordinary shares of TCL Industries (Malaysia) Sdn Bhd (TCLM) against the Reserves of the Company. The losses made by TCL Malaysian Joint Venture are being written down by TCL in India. This further confirms no injury to TCL/ local Industry. TCL has an exposure of Rs. 3769 lakhs, in TCL Industries (Malaysia) Sdn Bhd., on account of advances/ debtors which would be recovered in near future.

- x. TCL been one of the largest producers in the world do not need any protection against imports from the government and have won export awards and therefore can compete internationally.
- xi. India's requirements of Maleic Anhydride are more than 30,000 tonnes per annum and imports are inevitable.
- xii. MAN is used for the production of Maleates. Imposition of ADD would lead to imports of Maleates, thus leading to closure of local industry and vast unemployment. Maleates can be substituted by Acrylates, Vinyl Acetate copolymers etc produced indigenously and likely to affect adversely the Maleates Industry.

5. Submissions made by Exporter M/s D.D.International on behalf of Shanxi Regent Works, China PR

- i) The raw material prices of MAN has undergone a great change in the year 2009 as compared to the year 2008.
- ii) Anti dumping duty has proved to be a serious block to exports.
- iii) India has no domestic manufacturers.
- iv) TCL has built a MA manufacturing facility in Malaysia.
- v) Once TCL factory in Malaysia is closed it cannot meet the MA demand in India.

6. Submissions made on behalf of the Importers;

Importers namely M/s Jaydip Agencies, Mechemco Resins Pvt Ltd, Rachna Plasticizers, KLJ Silvassa Plast, Visen Industries have provided the information in respect of the imports made during the POI and previous two years as follows:

Qty. in MT

Name of Importer	2006-07	2007-08	POI
Jaydip Agencies	***	***	***
Mechemco	***	***	***
Rachna Plasticizer	***	***	***
KLJ Silvassa	***	***	***
Visen	***	***	***
Total	1116.5	2593.1	2687.7

The imports made from subject countries namely China PR, Indonesia and Chinese Taipei during this period are as follows:

Qty in MT

Name of Importer	2006-07	2007-08	POI
Jaydip Agencies	***	***	***
Mechemco	***	***	***
Rachna Plasticizer	***	***	***
KLJ Silvassa	***	***	***
Visen	***	***	***
Total	1116.5	2353.1	1568.7

It has been submitted that majority of the imports are under advance license. Further, the sources of import have changed from subject countries to other countries namely Korea, Malaysia and Singapore. The imports from China during this period have also gone down substantially. The imports done by aforesaid importers together from China were 1116.5 Mt during 2006-07, 2353.1 MT during 2007-08 and 1472.75 MT during POI which comes to 981 MT on an annualized basis.

7. Rejoinders to the written submissions made subsequent to the Public Hearing

a) By Indian Chemical Council

The duty was inadequate for protecting the domestic industry as it was only a fraction of duty needed to provide adequate protection. Especially so, considering that most of the aggressive dumping took place during the period of 18 months when the investigation was on. The facts of this period were not considered while arriving at the Anti Dumping Duty. As a result, the only major gross route Maleic Anhydride producer in India had to idle the plant for two years. The ICC has reviewed the situation and recommends imposition of adequate protection against the dumping as required by the applicant so that the domestic industry can operate.

b) Polyester Resin Manufacturers' Association

- i) There are more than 100 UP Resin Manufacturers in country spread all over India. Almost all resin manufacturers are in SSI sector (now SME's) directly employing more than 5000 people. These resins are used as main raw material in manufacturer of Fibreglass Reinforced Plastics (FRP). There are more than 2000 FRP manufacturers in our country employing over 500000 people.
- ii) The current production of UPR in our country is 180000 TPA using over 20000 tons of Maleic Anhydride. Maleic Anhydride is an essential raw material for manufacture of Unsaturated Polyester Resins. The total consumption of Maleic Anhydride in our country is estimated at 40000 TPA.
- iii) Presently there is no Maleic Anhydride production in our country and the entire requirement is met through imports.
- iv) After the levy of anti dumping duty, M/S Thirumalai Chemicals had promised to not only maintain production of approximately 12000 TPA but also increase it to 18000 MTA to partially meet the requirement of domestic market. Instead they totally stopped their plant after the imposition of Anti dumping duty, and started supplying from their plant in Malaysia which had no antidumping duty.
- v) TCL, Malaysia routed this product through their trading arm Ranson PTE. Ltd., Singapore and further through their agent in India, BMG Chemicals Pvt., Ltd. Thus, they have almost monopolised the Indian market.
- vi) The other producers on whom antidumping duty was levied, lost their interest in Indian market to such an extent that many a times, they have refused to quote the prices. However, they supply materials to neighbouring countries and to the Middle East Unsaturated Polyester resin producers. The producers thus, enjoy a cost Advantage and are easily able to sell the material in the Indian market as can be seen from increased imports of UPR after levy of antidumping duty. This has

badly affected the domestic producers of UPR and if the situation continues they may be forced to close down.

- vii) We feel that M/S TCL has not represented fairly to the Government and it appears that they had no intention of starting their plant in India but instead seek protection so as to facilitate and support their Malaysian manufacturing operations.

c) By the domestic industry:

A. In respect of the Written submission filed by Polyester Resin Manufacturer's Association (PRMA):

- (i) **Re-para 4 to 8:** PRMA has made the very general statement that TCL had not submitted any evidence and information in connection with the change in circumstances that may lead to a review of the duty in force include factors such as change in Normal Value, Export price, landed price and Non-injurious price of the domestic industry. It is submitted that TCL has submitted the detailed information with respect to change in circumstances vide its letter dated 1st September, 2009.
- (ii) **Re Para 9 to 11:** PRMA has quoted some decisions of the authority namely Mid-Term review Anti-dumping investigation in the matter relating to imports of Ethylene-Propylene-Non-Conjugated-Diene-monomer (EPDM) Rubber originating in or exported from European Union, USA, China PR and Brazil and Final Findings dated August 6, 2009 issued by DGAD in Saudi Basic industries and Ors. V. Designated Authority, Ministry of Finance, 2006 ECR 106 (Tri-Delhi) to support its contention that no question of "injury" to the Domestic Producer arises on account of its negligible domestic production of the subject goods.
- (iii) It is submitted that PRMA has quoted a very limited portion of the decisions as per their requirements. However, if the decisions are considered properly, it can be established that the above mentioned decisions does not apply in the instant investigation.
- (iv) In both the above mentioned cases, the domestic industry has stopped production and they did not have any inclination to restart their production.

However, in the current investigation, it is not so. The domestic industry had not stopped the production. In fact, TCL had made several attempts to re-start but could not compete with dumped imports and had to shutdown plant after brief runs. It should also be noted that the TCL intends to start its production to reap the benefit of its investment.

(v) Further, the domestic industry's intention to restart its production is corroborated with the fact that TCL the plant is being maintained in running condition and all the employees are still on the rolls of the company and the plant and machinery is standing idle but for the brief periods during which production took place. TCL has no intention of stopping the production or disposing of the plant and machinery. It is only a temporary market set back that TCL is not able to produce MAN. With a little assistance from Government of India in the form of adequate antidumping duty against dumped imports that cause havoc in the Indian market, TCL will be right back in the business within a very short period.

(vi) **Re-para 12:** In the production process of Pthalic Anydride, either of Maleic Anhydride (MAN) or Fumaric Acid can be obtained as a by-product. While Mysore Petrochemicals Ltd produces MAN in the production process of Pthalic Anydride, TCL produces Fumaric Acid as a by-product in production process of Pthalic Anydride. It is submitted that TCL has not recovered MAN as a by-product in the production process of Pthalic

(vii) Anydride. TCL has set up a separate plant for the production of the MAN and the same can be verified by the authority. We hereby extend our invitation to the authority to verify the existence of the MAN plant at our factory premises.

(viii) **Re-para 13 to 22:** PRMA has contended that the review should be terminated on account of a break of casual link as TCL has plummeted its production during POR in order to make way for imports from their plant in Malaysia. The investment by TCL in its Indian plant is far higher than the investment in TCL Malaysia. Further, TCL Malaysia is under liquidation process. Hence, it is highly irrational and illogical to believe that domestic industry will shut down its profitable venture to protect the company which is already undergoing liquidation process.

(ix) However, as the Malaysian company itself is under liquidation process, one cannot say that we had stopped production in the Indian plant just to import the goods from Malaysian plant. Even if Malaysian plant uses better and more efficient feedstock, it would be imprudent to stop production in India and rely upon Malaysian production as the company is

already in liquidation. Therefore, there is no merit in their argument that TCL has closed the Indian plant only to import from their Malaysian plant.

- (x) Re-para 23: PRMA has made certain unsubstantiated allegations. The facts speak otherwise. If suppliers from the subject countries had refused to export goods to Indian customers, import volumes would have fallen. On the contrary, import volumes have increased by over 97% in the past 4 years. Thus, there is no merit in their argument.

B. In respect of written submission filed by Indian Plasticizers Manufacturers Association (IPMA):

- i. Imports by TCL: TCL has been importing substantial quantities from its related entity in Malaysia and being an importer it does not qualify as domestic industry and should be declared as an ineligible domestic producer for the purpose of rule 2(b). With regard to imports of the product concerned from Malaysia, Domestic Industry submits that Malaysia is not a subject country. Since Malaysia is not a subject country, the exclusion clause provided under Rule 2 (b) is not attracted at all. In view of the same, imports from Malaysia shall have no impact on the outcome of this investigation.
- ii. **Benzene Vs. Butane Plant:** IPMA has claimed that we have mentioned the manufacture of MAN using Benzene technology is unviable is wrong. We have stated that while the prices of Benzene have increased, the landed value of MAN has not increased. This has prevented the domestic industry from increasing prices of MAN in commensurate with the increase in its cost of production.
- iii. Further, the issue of use of Benzene vs. Butane in the production of MAN had also been raised in the original investigation. In the original investigation, it was held that since exporters, themselves, use Benzene route, they cannot claim that the Indian domestic producer should not use Benzene route. In the current investigation, none of the

exporter has co-operated or provides any information which proves that they are using Butane for the production of MAN. When, both the exporter and the domestic industry are using the same technology, the question of usage of Butane does not arise.

- iv. TCL has a minority stake in its joint venture in TCLM. The minority stake in the related entity –TCLM does not mean that TCL should also use the same technology as used by Malaysian company.
- v. **Imports from TCLM:** IPMA claim that TCL have mala-fide intention of protecting and giving unjust benefit to Malaysian Joint Venture at the cost of Indian consumer industry is untenable. In addition to the submissions made in the preceding paragraphs, it should be noted that Malaysian JV is not a new venture. It has been in operation for more than 14 years. During all these years, TCL has been manufacturing the product concerned with some minimal or sporadic imports of the product concerned from Malaysia. It is submitted that imports from TCL has increased recently only during 2008-09. But, the reason for importation of product concerned from Malaysia is continuous dumping of MAN from the subject countries and not as projected by IPMA.
- vi. IPMA claims that there is no injury to the domestic industry as their profits had increased. It must be noted that the profits of the company as a whole has increased as their operations relating to other products such as Phthalic Anhydride, fumaric acid and other food acids. Since the MAN plant is shut down except for intermittent production, TCL did not earn any money on its operations relating to MAN.
- vii. Further, IPMA states that the losses suffered by TCL Malaysia joint venture are being written down by TCL India and accordingly there is no injury to the domestic industry. This argument lacks basic understanding what injury is in an antidumping investigation. TCL has never claimed that they are suffering losses on account of writing down

the value of investment in the Malaysian JV. The loss on this account has not been loaded to the loss on the Indian operations relating to MAN. This issue has nothing to do with the injury suffered by the domestic industry on account of dumped imports from the subject countries.

- viii. **No-provision is required for TCL's exposure in TCLM:** TCL's expectation of recovery of its exposure of Rs 3769 lakhs in TCLM on account of advances/debtors does not mean that TCLM's operations are viable. The investment as share capital and loan are different. While the investment in share capital is part of the capital of a company, the loan and advance are liabilities of a company. Under the liquidation process, the settlement of loan and advances are given preference over the owner's capital. TCL expects that although, the net worth of TCLM has eroded, the assets of TCLM are sufficient to meet its liabilities. Hence, TCL has not considered it necessary to create the provision for the same.

EXAMINATION BY THE AUTHORITY

8. The Authority notes that no response has been submitted either by any producer/ exporter from the subject countries except by M/s D. D. International, as detailed above. Moreover the applicant domestic industry has stopped production and the other domestic producer has not provided costing and injury related information. In view of this, the Authority considers that it is not necessary to determine whether the current imports are at dumped prices and if so, what is the extent of dumping, as the Authority considers that determination of injury to the domestic industry is not relevant to the present investigations as there is insufficient information on record to determine whether the domestic industry in India has suffered injury within the meaning of Rule 11.

9. The product under consideration involved in the original investigation and also in the present review application is Maleic Anhydride (MAN) originating in or exported from the China PR, Chinese Taipei and Indonesia.

10. The product under consideration is 'Maleic Anhydride (MAN) (also referred to as subject goods). MAN is an organic acid anhydride ($C_2H_4O_3$), generally available in pillow shaped briquette form or in molten form. Both forms are

considered within the product under consideration in the investigation. MAN is used to manufacture a wide range of products like unsaturated polyester resins, alkyd resins, paper sizing chemicals, insecticides and fine chemicals. MAN is classified under ITC (HC) subheading 29171400. However, the customs classification is indicative only and is in no way binding on the scope of present investigation.

11. The authority notes that none of the interested parties has raised any argument on the issue of product under consideration. The Authority, therefore, has considered the same scope of the product under consideration as was considered in the final findings earlier notified. Further, the Authority proposes to hold that the goods produced by the domestic industry are like articles of the subject goods imported from the subject countries.

12. The Authority examined the various applicable statutory provisions in the light of the arguments raised by the interested parties. The Authority observes as follows with regard to various legal provisions:

(a) The present investigations are being conducted under Section 9A(5) and Rule 23, which provides as follows

23. Review. - (1) *The designated authority shall, from time to time, review the need for the continued imposition of the anti-dumping duty and shall, if it is satisfied on the basis of information received by it that there is no justification for the continued imposition of such duty recommend to the Central Government for its withdrawal.*

(2) *Any review initiated under sub-rule (1) shall be concluded within a period not exceeding twelve months from the date of initiation of such review.*

(3) *The provisions of rules 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, and 20 shall be mutatis mutandis applicable in the case of review.*

(b) It is noted that the provisions of Rule 11 are fully applicable in case of midterm reviews as well. Rule 11 provides as follows

11. Determination of injury. - (1) *In the case of imports from specified countries, the designated authority shall record a further finding that import of such article into India causes or threatens material injury to any established industry in India or materially retards the establishment of any industry in India.*

(2) *The designated authority shall determine the injury to domestic industry, threat of injury to domestic industry, material retardation to*

establishment of domestic industry and a causal link between dumped imports and injury, taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on price in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles and in accordance with the principles set out in Annexure II to these rules.

(c) It is observed that the Authority is required to determine injury to the domestic industry. Further, manner of determining injury to the domestic industry has been described in detail under Rule 11 and Annexure II to the Rules.

(d) Rule 2(b) defines domestic industry and provides as follows –

(b) "domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in which case [such producers may be deemed] not to form part of domestic industry

13. Having regard to various legal provisions, it is to be noted that-

- (a) the Authority is required to determine injury to the domestic industry in the present case. TCL also concedes that the Authority is required to determine injury to the domestic industry in the present case. TCL has in fact pleaded the dumped imports have caused injury to the domestic industry. TCL has argued that the dumped imports have led to continued material injury and are retarding establishment of domestic industry in India,
- (b) Rule 11 provides determination of injury in respect of "domestic industry". Such domestic industry has been defined under Rule 2(b) as domestic producers whose collective output constitutes "a major proportion" in Indian production.
- (c) Some of the interested parties arguing revocation of anti dumping duties have argued that TCL has resorted to significant imports of the product under consideration from Malaysia. The Authority considers it unnecessary to consider whether imports made by TCL from Malaysia should be examined in the light of discretionary exclusion provision under Rule 2(b), as the Authority observes that the same will not alter the present determination.

- (d) Only TCL has participated in the present investigations and has argued that imports of the product under consideration have caused injury to the domestic industry on the basis of information pertaining solely to TCL. It is not the argument of TCL that the dumped imports have caused injury to other domestic producers. Mysore Petrochemicals Ltd (MPL) has neither provided any injury information to the Authority nor claimed that the imports have caused injury to MPL.
- (e) Since MPL has not cooperated with the Authority and has not provided injury information, the Authority has been constrained to consider whether TCL constitutes domestic industry within the meaning of Rule 2(b) and whether injury to the domestic industry can be determined based solely on information provided by TCL. The Authority is constrained to note that TCL cannot be considered "domestic industry" within the meaning of Rule 2(b), as production of TCL constitutes a meagre 19.6 % of Indian production as per the table below:

Year	Production			TCL % in Total Production
	TCL	MPCL	Total	
2005-06	***	***	***	81.0%
2006-07	***	***	***	79.8%
2007-08	***	***	***	43.3%
2008-09	***	***	***	22.7%
POI	***	***	***	19.6%
POI-Annualized	***	***	***	19.6%

Thus, the production of TCL does not constitute a major proportion in the Indian production.

- (f) With regard to the argument of TCL that dumping has prevented the company from producing and selling the product, the Authority notes that the issue is relevant to injury determination and not in deciding scope of the domestic industry. Only quantum of Indian production is relevant in deciding scope of domestic industry. Undisputedly, the

quantum of Indian production during the POI was 4310 MT, of which only *** MT is accounted for by TCL, rest all being held by MPL.

- (g) The facts of the present investigation does not require the Authority to consider whether the proviso to Rule 2(b) dealing with segmented markets is relevant to the present case; nor the present industry is a fragmented industry involving large number of producers.
- (h) TCL and MPL have been operating in the same domestic market. Undisputedly, MPL has almost maintained its production and market share whereas TCL has got reduced to mere 1.57% market share in consumption in India. It remained unexplained how MPL has been able to maintain its production and market share under the same market situations.
- (i) It is clarified that Rule 5 is not applicable to the present review. Standing of the petitioner is not required to be seen in the present investigations. However, injury to the domestic industry under Rule 11 (which is undisputedly applicable in case of reviews) and standing of the applicants under Rule 5 are two distinct and different requirements.

14. Comments to the Disclosure Statement

a) M/s Indian Plasticizers Manufacturers Association have reiterated their earlier submissions and have stated that M/s Indian Chemical Council have never participated in the anti dumping proceeding either in the earlier or Review Investigations but have submitted a rejoinder to the written submissions. Further, the liquidation of their Malaysia unit could be due to mismanagement, financial constraints and other extraneous factors. The manufacture of Maleate Plasticizers, unsaturated Polyester Resins etc, major consumers of MAN are in the Small Scale Sector.

b) M/s. Polyester Resin Manufacturer's Association have reiterated their earlier submissions and have submitted that the information forming the basis for the initiation as presented by TCL remains inaccurate and inadequate. Further, there is no causal link between the alleged dumped imports of the subject goods by the subject countries and the alleged injury to the Domestic Industry as the Petitioner's Indian operations have drastically plummeted during the injury period to make way for the imports from Malaysia and Singapore. Since there is no Domestic Industry, there is no question of any dumping or injury analysis. The continued imposition of anti dumping duty on the subject goods has had

cascading effects on the prices of the end products and adversely affect the market competitiveness of the domestic manufacturers of the end products.

c) M/s Thirumalai Chemicals Ltd.(TCL),

- i. It is submitted that the statements of the Authority in respect of composition of Domestic industry inherently contradict each other. At one hand, the Authority agrees that the standing requirement as envisaged under Rule 5 is not required to be fulfilled in a Review Investigation. However, on other hand, the Authority states that since TCL accounts only for 19.6% of total production during POI, it cannot determine injury for a domestic industry within Rule 2(b). The purpose of anti-dumping duty is to accord continued protection to domestic producers of like product who have suffered or likely to suffer material injury.
- ii. The Authority has failed to appreciate the distinction between the production routes followed by MPL and TCL. The subject goods i.e. MAN is produced by MPL as a by-product while producing Phthalic Anhydride. Therefore, the cost of production of MAN for MPL is minimal and it is able to sell it to its customers at quite low prices. Whereas, TCL produces MAN as an independent product. It operates a dedicated plant solely for the production of MAN. The total amount of investment made in this plant is worth approximately Rs. *** crores today. Therefore, it is unfair to judge the performance of TCL as against MPL.
- iii. Further, even if it is assumed that TCL does not constitute domestic industry within Rule 2(b), the same does not preclude the continuation of anti-dumping duty. The anti-dumping protection is also accorded in cases where dumped imports cause material retardation of establishment of a domestic industry. The domestic industry is striving hard to increase its production in the Indian market and to find place for its indigenous manufactured product in India. However, the dumped imports from subject countries had barred the domestic industry from commercialization of its production. Hence, the dumped imports have not only caused the injury to the domestic industry, but it has also

materially retarded the establishment of the domestic industry. The Authority has not examined this aspect of the case at all.

- iv. Furthermore, the Authority is not obligated to assess present injury in a review investigation. Therefore, the fact that TCL constitutes only 19.6% of total production is of no consequence for injury assessment. The Hon'ble Supreme Court, in *Rishiroop Polymers Pvt Ltd. v Designated Authority*, 2006 (196) E.L.T. 385 (S.C.), has considered the purpose and scope of review in following terms:

Otherwise also, we are of the opinion that scope of the review inquiry by the Designated Authority is limited to the satisfaction as to whether there is justification for continued imposition of such duty on the information received by it. By its very nature, the review inquiry would be limited to see as to whether the conditions which existed at the time of imposition of anti-dumping duty have altered to such an extent that there is no longer justification for continued imposition of the duty. The inquiry is limited to the change in the various parameters like the normal value, export price, dumping margin, fixation of non-injury price and injury to domestic industry. The said inquiry has to be limited to the information received with respect to change in the various parameters. The entire purpose of the review inquiry is not to see whether there is a need for imposition of anti-dumping duty but to see whether in the absence of such continuance, dumping would increase and the domestic industry suffer.

- v. A review by its very nature is limited to examination of "changed circumstances" to determine the need for continued imposition of anti-dumping duty. In the present case, it is apparent on the face of it that TCL is not able to manufacture subject goods due to intense dumping of goods. The fact that TCL's production has been erratic further strengthens the justification for continued imposition of duty at a higher rate. Should the Authority take the opposite view it would have disastrous consequences not only in this case but also in future cases. Taking advantage of such a view, any exporters would further intensify their dumping after original investigation and systematically

kill the domestic producers. Upon complete or partial stoppage of production, the exporter would request for initiating a mid-term review arguing that there is no need for continuation of duty as there is no domestic industry at all. This would go against the very purpose of trade remedy measures like anti-dumping law. In fact, the Canada International Trade Tribunal was faced with a similar question in an Anti-dumping Review Investigation u/s 76(2) of the Special Import Measures Act concerning imports of Carbon Steel Welded Pipe (Finding attached as Annexure-I). In that case, even after 17 years of protection of anti-dumping duty, the domestic industry had closed plants and its financial condition was largely poor. The Tribunal held as follows:

"With respect to the issue of injury, the Tribunal noted that, throughout the 1990s, the domestic industry had closed plants and rationalized production and, at the same time, made substantial investments in new, state-of-the-art production facilities. Nonetheless, sales had been stagnant, the industry had been operating at low levels of capacity, and its overall financial performance had been poor. In fact, the Tribunal noted that the standard pipe industry in Canada had had a few good years over the last two decades, despite the protection afforded by 17 years of anti-dumping duties on Korean pipe. This fact suggested to the Tribunal that there were problems within the industry that went beyond what could be rectified by anti-dumping measures. In the Tribunal's view, continuing the order would not have automatically improved the domestic industry's current performance; however, rescinding the order would have almost certainly made the industry materially worse off."

- vi. In the above investigation, the Tribunal also found that there were other reasons than dumping which had also caused injury to the domestic industry. Yet the Tribunal was of the view that removal of anti-dumping duty would certainly further aggravate the situation of the domestic industry. Therefore, it would be unreasonable on part of the Authority to conclude that there is no need for continued imposition of anti-dumping duty just because TCL's production volume and its share in the total Indian production has declined. All that the Authority is required to see whether in the absence of anti-dumping

duty, dumping would increase and TCL would suffer further injury. It is evident that if the anti-dumping duty is withdrawn, the dumping would further intensify and the TCL would be systematically eradicated from the market. The fact that TCL's production has been falling actually proves the serious and alarming state of injury caused to TCL.

- vii. The above contention is further buttressed in the light of the Appellate Body Report in United States – Sunset Reviews of Anti-Dumping Measures on Oil Country Tubular Goods from Argentina, WT/DS268/AB/R

279. The lack of a sufficient textual basis to apply Article 3 to likelihood-of-injury determinations is not surprising given "the different nature and purpose of original investigations, on the one hand, and sunset reviews, on the other hand", which the Appellate Body emphasized in US – Corrosion-Resistant Steel Sunset Review. Original investigations require an investigating authority, in order to impose an anti-dumping duty, to make a determination of the existence of dumping in accordance with Article 2, and subsequently to determine, in accordance with Article 3, whether the domestic industry is facing injury or a threat thereof at the time of the original investigation. In contrast, Article 11.3 requires an investigating authority, in order to maintain an anti-dumping duty, to review an anti-dumping duty order that has already been established—following the prerequisite determinations of dumping and injury—so as to determine whether that order should be continued or revoked.

280. Given the absence of textual cross-references, and given the different nature and purpose of these two determinations, we are of the view that, for the "review" of a determination of injury that has already been established in accordance with Article 3, Article 11.3 does not require that injury again be determined in accordance with Article 3. We therefore conclude that investigating authorities are not mandated to follow the provisions of Article 3 when making a likelihood-of-injury determination.

- viii. Under the Indian Anti-dumping Law, a mid-term review is carried out pursuant to the mandate provided in Section 9A(5) of the Customs Tariff Act, 1975. The said provision is akin to Article 11.3 of WTO: AD Agreement. In fact, Indian law has not distinguished the mid-term review and sunset review as it appears in the AD Agreement. Thus, Section 9A (5) which is akin to Article 11.3 applies to mid-term reviews also. Therefore, in the light of the Report of the

34492/10-8

Appellate Body, the Authority is not required to re-determine injury that was already established in the original investigation. Therefore, the question of finding a domestic injury in terms of Rule 2(b) also does not arise as there is no need to re-establish injury as it is done in an original investigation.

- ix. In the light of the foregoing facts and legal arguments, it is submitted that the circumstances prevailing at the time of the original investigation has materially changed. The subject countries have indulged in even more intensified dumping of subject goods. Dumped goods have caused material injury to the domestic industry. Dumping has also materially retarded the establishment of the domestic industry. Hence, it is requested the Authority may suitably increase the present levels of anti-dumping duty in order to protect the domestic industry.

15. Examination by the Authority

The arguments raised by TCL in response to disclosure statement have been examined by the Authority and the Authority notes as follows:

- a) TCL has argued that the statement of the Authority is contradicting in as much as the Authority agreed that the standing requirement is not pre-requisite under Rule 5 and at the same time, the Authority cannot determine injury to the domestic industry because production of TCL is only 19.6% of total production. The Authority holds that there is no contradiction in the said statement. Standing requirements under Rule 5 and scope of domestic industry under Rule 2(b) are two different requirements. Since rule 23 does not refer to Rule 5, the Authority concluded that standing is not a requirement under the Rules for the purpose of initiation of Mid Term Review. However, it is only with regard to an application filed before the Designated Authority requesting initiation of investigations. Since Rule 23 does not refer to Rule 5, the Authority is justified in initiating the investigations regardless of the share of petitioner's production in Indian production. However, if share of petitioner's production does not constitute a major proportion in Indian production within the meaning of Rules, such petitioner cannot constitute the domestic industry within the definition of Rule 2(b). The Authority has consistently taken the view that if share of petitioner is below 25%, such share cannot constitute a major proportion within the meaning of Rule 2(b), barring the exceptions given in rule 2(b) itself. In the instant case, admittedly, there are two producers of the product under consideration. Production of other company is above 80% and the petitioner's production is below 25%. The Authority is therefore, unable to consider the petitioner as domestic industry for the purpose of Rule 2(b). Further, as noted elsewhere, the Authority is required to determine injury after defining domestic industry and thereafter assessing injury to such domestic industry. Since in the instant case, the Authority is unable to

consider TCL as a domestic industry, the Authority is unable to determine injury to the domestic industry.

- b) With regard to difference in production routes followed by TCL and MPL, the Authority notes that Rule 2(b) does not distinguish between different routes leading to production of the product concerned. Rule 2(b) refers to "production" and thus routes of production are wholly irrelevant. Even if the production is through by product route, it is nevertheless constitutes production for the purpose of anti-dumping rules. Thus the production routes are entirely immaterial in defining scope of domestic industry.
- c) With regard to the argument of TCL that even if it does not constitute domestic industry, the same does not preclude continuation of anti-dumping duties and the rules recognize 'material retardation to establishment of domestic industry', the Authority notes that the current application has been filed by TCL for seeking upward revision of anti-dumping duties and by different users associations namely M/s Indian Plasticizers Manufacturers Association and M/s Polyester Resin Manufacturer's Association seeking withdrawal of anti-dumping duties. Even if it is appreciated that Rules permit continuation of anti-dumping duties and Rules recommends material retardation to establishment of the domestic industry as a form of injury, both provisions pre-suppose consideration of the "domestic industry" by the Authority. Even material retardation to establishment of domestic industry pre-supposes a determination with regard to a "domestic industry". Further, continued injury to the domestic industry also pre-supposes a determination with regard to "scope of domestic industry". In other words, no anti-dumping duties can be extended/enhanced or modified unless the Authority is able to establish a "domestic industry" within the meaning of Rule 2(b), whose data can be relied upon for determination of injury. In the instant case, the Authority is unable to establish companies whose data can be relied upon to determine injury. While TCL production is below the minimum threshold of 25%, other domestic producer has not cooperated with the Authority with relevant injury information. Since the Authority is unable to define the constituents of domestic industry in the present case, the Authority is precluded from considering whether domestic industry has suffered or is likely to suffer injury.
- d) With regard to the argument that the dumped imports have barred the domestic industry from commercializing the production, Authority notes that TCL has failed to establish existence of domestic industry within the meaning of Rule 2(b). Further, the question of commercialization of production cannot be considered for a company which is already in commercial production and who subsequently curtailed its production.
- e) With regard to the decision of the Hon'ble Supreme Court in Rishiroop Polymers Pvt Ltd. v Designated Authority by TCL, the Authority notes that the said decision is based on "constitution of domestic industry". But, in the instant case, the Authority is unable to constitute a domestic industry, question of application of Hon'ble Supreme Court decision will not arise.

- f) With regard to TCL argument that intensified dumping of the product is resulting in erratic production by TCL and the same justifies continued imposition of anti-dumping duties at higher rate, the Authority notes that consideration of TCL data for the purpose of assessing injury is feasible only if the Authority comes to a conclusion that TCL constitutes domestic industry within the meaning of Rule 2(b). Given the conclusion of the Authority that TCL does not constitute domestic industry, performance of TCL is wholly irrelevant.
- g) TCL has drawn attention of the Authority to the decision of the Canadian authorities in the matter of carbon steel welded pipes case. The Authority however holds that TCL has not established that the said decision of the Canadian authorities is without defining a domestic industry and its constituents in that case. In the present case, as stated before, the Authority is not able to establish scope of domestic industry whose injury can be examined.
- h) TCL has argued that the Authority is required to consider whether dumping would increase in the absence of anti-dumping duties and whether TCL would suffer further injury. The Authority, however, notes that the Rules do not envisage examining injury to a company. The rules envisage examination of "injury to the domestic industry". The domestic industry for the purpose is required to be defined/constituted having regard to the requirements of Rule 2(b).
- i) TCL has referred to the decision of the WTO in the matter of United States – Sunset Reviews of Anti-Dumping Measures on Oil Country Tubular Goods from Argentina the Authority holds that the said decision is again based on positive determination with regard to "domestic industry". In the present case, however, the Authority is unable to determine the domestic industry whose injury can be examined.
- j) TCL has argued that Section 9A(5) is akin to Article 11.3, the Designated Authority and Indian law has not distinguished between Mid Term Review and Sunset Review. The Authority considers that the issue is entirely irrelevant. The Authority is required to define/determine the scope of domestic industry whether it is a fresh investigation or a Mid Term Review or a Sunset Review. If the constitution of domestic industry itself cannot be established, the Authority cannot establish existence or otherwise of injury to the domestic industry.

16. Conclusion

After careful consideration of submissions made by various interested parties and TCL in particular, including their comments on disclosure statement and having regard to legal provisions, the Authority holds that the Rules require examination of "injury to the domestic industry" in the present case, for which the Authority is required to define/ determine "domestic industry". In the present case, production of TCL not being a major proportion in Indian production, the Authority is unable to consider TCL as a domestic industry. The only other domestic manufacturer

commands production of above 80% of the Indian production and has not participated in the present investigation and has not provided any information relevant to assessment of injury to the domestic industry. The Authority, therefore, is unable to determine whether the alleged intensified dumping of the product is causing or is likely to cause injury to the domestic industry in any of its form laid down under the Rules. Further, in the light of the foregoing, the Authority is unable to determine whether such imports of the product under consideration have caused injury to the domestic industry in the absence of sufficient injury information from "domestic industry". In view of the same, the Authority has not made determination with regard to the extent/degree of dumping from the subject countries, nor has the Authority examined whether the possible injury is because of apparent dumped imports.

17. FINDINGS

- a. The Authority, after considering the foregoing and as well as the comments on the disclosure statement, concludes that there is no domestic industry affected from the imports from the subject countries.
- b. In view of the above, the Designated Authority considers it appropriate to recommend discontinuation of Anti-dumping duty in force in respect of the subject goods originating in or exported from the subject countries as notified vide Notification No. 105/2008-Customs dated 18th September 2008 in terms of Section 9 (A) (5) of the Act.
- c. An appeal against the orders of the Central Government that may arise out of this recommendation shall lie before the Customs, Excise and Service tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act.

P. K. CHAUDHERY, Designated Authority